अध्याय

11

सहायक कार्यक्रम

सहायक कार्यक्रम

11.1 सूचना एवं जन जागरुकता कार्यक्रम

11.1.1 भारत वैश्विक अक्षय ऊर्जा परिवर्तन का एक भाग है और अक्षय ऊर्जा क्षमता की दृष्टि से विश्व के पांच शीर्ष देशों में शामिल है। मंत्रालय ने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सुगम नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए सुव्यवस्थित रूप से कार्य किया है। सौर तथा पवन विद्युत की बिक्री के लिए अंतर–राज्य शुल्कों की माफी; अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता ट्रेजेक्टरी; सौर तथा पवन विद्युत की खरीद के लिए स्पर्धात्मक बोली दिशानिर्देश; तापीय विद्युत केन्द्रों के उत्पादन और शिड्यूलिंग में लचीलापन; सौर कूकर कार्यक्रम; सौर–पवन हाइब्रिड नीति; टेक–ऑफ के आश्वासन से जुड़े सौर पीवी उत्पादन; अटल ज्योति योजना, पीएम–कुसुम और सौर पीवी प्रणालियों की स्थापना के लिए मानक आदि कुछ प्रमख पहल हैं। इन सभी पहलों को सही तरीके से लागू करने के लिए अक्षय ऊर्जा के लाभ और उपयोग को जनता तक पहुंचाने, सूचना का प्रचार और प्रसार आवश्यक है। इस परिप्रेक्ष्य में, अक्षय ऊर्जा के लिए आई एंड पीए कार्यक्रमों की संकल्पना की जाती है और क्रियान्वयन के लिए इनका विकास किया जाता है।

11.1.2 कार्यक्रम का क्रियान्वयन सरकारी माध्यमों अर्थात् (i) ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्यूनिकेशन (बीओसी) (ii) भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी), (iii) दूरदर्शन, (iv) आल इंडिया रेडियो (एआईआर), (v) अक्षय ऊर्जा के लिए राज्य नोडल विभाग / एजेंसियां और (vi) एनजीओ / शैक्षणिक संस्थान आदि और मंत्रालय तथा अन्य संबंधित संस्थानों / संगठन के माध्यम से भी राष्ट्रीय महत्व की प्रदर्शनियों में हिस्सेदारी करके किया जा रहा है। यह अपने तीन स्वायत्त संस्थानों अर्थात् नाइस, नीवे और एसएसएस–नीबे तथा दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) अर्थात् इरेडा और सेकी के माध्यम से व्यापक रूप से सूचना और जागरूकता प्रदान कर रहा है।

11.1.3 वर्ष के दौरान, अक्षय ऊर्जा के लिए मीडिया रणनीति के व्यापक ढ़ांचे के तहत निम्नलिखित आई एंड पीए गतिविधियां विकसित और कार्यान्वित की गईं:–

i. मंत्रालय ने वर्चुअल प्लेटफार्म पर दिनांक 26 से 28 नवम्बर, 2020 तक री–इन्वेस्ट के तीसरे संस्करण का आयोजन किया। तीसरे री–इन्वेस्ट के लिए इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए प्रचार प्रसार किया गया।

ii. अक्षय ऊर्जा पर विभिन्न कार्यक्रमों/प्रदर्शनियों के लिए विभिन्न संगठनों को लोगो सपोर्ट दिए गए।

iii. मंत्रालय के तीन संस्थानों और दो पीएसयू के माध्यम से सोशल मीडिया पर कार्यक्रमों, योजनाओं, उपलब्धियों को नियमित रूप से पोस्ट किया जाता है।

iv. आईइसी गतिविधियों के लिए पीएम कुसुम, रूफटॉप सौर, री–इन्वेस्ट पर लघु फिल्मों का निर्माण किया तथा भारत के अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के अवसरों पर पुस्तिका जारी की।

11.2 योजना और समन्वयन

11.2.1 मंत्रालय का योजना और समन्वयन प्रभाग, मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों, विभिन्न नीति और राजकोषीय सुधारों से संबंधित सभी मामलों के लिए समग्र योजना और समन्वय के लिए जिम्मेदार है। इसके कार्यों में मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रम प्रभागों और अन्य संबंधित मंत्रालयों और विभागों अर्थात् प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ), नीति आयोग, विदेश मंत्रालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड (पीआईबी) तथा राज्य नोडल एजेंसियां (एसएनए) और ऊर्जा या अक्षय ऊर्जा विभाग सहित राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ निकट संपर्क बनाए रखना शामिल है।

11.2.2 प्रभाग द्वारा वर्ष 2020–21 के दौरान संचालित गतिविधियों में मुख्यतः ग्रिड और ऑफ ग्रिड अक्षय विद्युत में प्राप्त उपलब्धियों के लिए डेटा बेस का संकलन और नियमित अपडेशन, अनुदानों की मांग के संबंध में और जांच के

लिए चयनित अन्य विशिष्ट विषयों से संबंधित ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के लिए रिपोर्ट तैयार करना, प्रमुख उपलब्धियों/पहलों की मासिक रिपोर्ट तथा की गई कार्रवाई की मासिक रिपोर्ट तैयार करना शामिल है। इस कार्य में पीएमओ/कैबिनेट सचिवालय/पीआईबी आदि के लिए मासिक अ.शा. पत्र, कार्रवाई नोट और विभिन्न बैठकों के लिए बहु–क्षेत्रीय इनपुट/ब्रीफ, माननीय राष्ट्रपति/माननीय प्रधानमंत्री के भाषणों के लिए इनपुट, मंत्री/माननीय वित्त मंत्री/एमएनआरई के माननीय मंत्री/सचिव, सांसदों और अन्य महानुभावों को उत्तर देना भी शामिल है।

प्रश्नावलियों/संसद प्रश्नों के उत्तर भी तैयार किए जाते हैं, जिनमें कई योजनाएं/कार्यक्रम, मंत्रालय के विभिन्न पोर्टल जैसे ई–समीक्षा, प्रगति, आदि का अपडेशन शामिल है। अन्य मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त विभिन्न मसौदा कैबिनेट नोट, व्यय वित्त समिति (ईएफसी), स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) और अन्य मंत्रालयों तथा विभागों से प्राप्त प्रश्नों आदि पर टिप्पणियों का समयबद्ध संकलन, बजट के लिए आउटपुट–आउटकम रूपरेखा तैयार करना, आदि कार्य शामिल हैं।

11.3 मानव संसाधन विकास

11.3.1 एमएनआरई की मानव संसाधन विकास (एचआरडी) योजना, उच्च अध्ययन और अनुसंधान पाठ्यक्रमों में आर एंड डी को प्रोत्साहित करने तथा अक्षय ऊर्जा में शैक्षणिक संस्थाओं के छात्रों और अनुसंधान विद्वानों को फेलोशिप देने सहित सभी स्तरों पर मानवश्रम के लिए सहायता प्रदान की जाती है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा में परा–स्नातक और डॉक्टोरल स्तरों पर उच्च डिग्री पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं के लिए उनके पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं के उन्नयन के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है। मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना करने, चालू करने, प्रचालन और रखरखाव करने के लिए प्रशिक्षित मानवश्रम के सृजन के लिए 50,000 कुशल मानवशक्ति को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वर्ष 2015 में ***सूर्यमित्र*** नामक कौशल विकास कार्यक्रम तथा पवन ऊर्जा में कौशल विकास के लिए ***वायुमित्र*** कार्यक्रम की शुरुआत की गई।

मानव संसाधन विकास योजना के विभिन्न घटक निम्नानुसार हैं:

» सभी स्तरों पर कौशल विकास पर ध्यान देने के साथ अक्षय ऊर्जा के विभिन्न पहलुओं पर अल्प–कालिक प्रशिक्षण के आयोजन के लिए शैक्षिक और अन्य संगठनों को सहायता देना।

» सौर जल पंपिंग और पवन ऊर्जा में सूर्यमित्र तथा अन्य कौशल विकास कार्यक्रम

» मंत्रालय द्वारा निम्नानुसार फेलोशिप कार्यक्रमों को सहयोग दिया जाता है:

  * एमएससी/एमटेक/पीएचडी/पीडीएफ डिग्री पाठ्यकम के लिए राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा फेलोशिप (एनआरईएफ) योजना

  * सौर ऊर्जा में नवोन्मेषी सोच के साथ अनुसंधान संस्थानों में कार्य कर रहे प्रमुख वैज्ञानिकों के लिए राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा विज्ञान फेलोशिप योजना।

» प्रयोगशाला और पुस्तकालय के उन्नयन हेतु उच्च शिक्षण संस्थाओं को सहायता

» व्यक्तिगत विशेषज्ञों या विशिष्ट संस्थान के माध्यम से पाठ्यक्रम सामग्री का विकास

» राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा इंटर्नशिप योजना

11.3.2 राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा फेलोशिप योजना

एमएनआरई ने एनआरईएफ योजना के तहत फेलोशिप या छात्रवृत्ति प्रदान करते हुए 11 चयनित शैक्षिक संस्थानों में अक्षय ऊर्जा में एमएससी, एमटेक, पीएचडी पाठ्यक्रमों जैसे उच्च अध्ययन के लिए छात्रों और विद्वानों को अपनी

सहायता देना जारी रखा। वर्ष 2020–21 के दौरान, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से 37 पीएचडी, **26** एमटेक या एमई और **20** एमएससी फेलोशिप प्रदान की गईं जिसमें से 17 छात्रों को एमटेक या एमई डिग्री और 10 छात्रों को एमएससी (अक्षय ऊर्जा) डिग्री जारी की गई। सहायता प्राप्त संस्थानों की सूची **तालिका 11.1** में दी गई है।

तालिका 11.1: वर्ष 2020–21 के दौरान एनआरईएफ योजना के तहत एमएनआरई फेलोशिप द्वारा सहायता प्राप्त संस्थान

क्र. सं.	ऐसे संस्थान जिन्हें फेलोशिप प्रदान की गई (एमएससी, एमटेक, जेआरएफ/एसआरएफ (पीएचडी))
1.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर
2.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की
3.	पुणे विश्चविद्यालय, पुणे, महाराष्ट्र
4.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुडुचेरी
5.	श्री माता वैष्णों देवी विश्वविद्यालय, कटरा, जम्मू एवं कश्मीर
6.	जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता
7.	कोचीन युनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, कोच्ची
8.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नालॉजी, शिबपुर, पश्चिम बंगाल
9.	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
10.	राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (एनपीएल), सीएसआईआर, नई दिल्ली
11.	झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, रांची

11.3.3 कौशल विकास कार्यक्रम और प्रशिक्षण

11.3.4 सूर्यमित्र प्रशिक्षण: वर्ष 2020 तक 50,000 सूर्यमित्रों को प्रशिक्षित करने के लिए मंत्रालय ने वर्ष 2015 में सूर्यमित्र कौशल विकास कार्यक्रम की शुरुआत की और मार्च 2020 तक 47,166 सूर्यमित्रों को प्रशिक्षित किया। वर्तमान वर्ष के लिए, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (नाइस), गुरुग्राम को 4,500 सूर्यमित्रों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। इनका आयोजन मार्च 2020 में नाइस द्वारा जारी रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से देशभर के विभिन्न राज्यों में शामिल किए गए प्रशिक्षण केन्द्रों और भागीदार संगठनों के माध्यम से किया जा रहा है। कुल 47,166 सूर्यमित्रों को मार्च 2020 तक प्रशिक्षित किया गया है, सूर्यमित्र कार्यक्रम 2015–20 के अनुसार राज्य–वार प्रगति। **तालिका 11.2** में दर्शाई गई है।

तालिका 11.2 : वर्ष 2015–16 से 2019–20 के दौरान विभिन्न राज्यों में प्रशिक्षित सूर्यमित्रों की संख्या में प्रगति

क्र. सं.	राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों	मार्च 2020 तक लक्ष्य	2015–16 में प्रशिक्षित	2016–17 में प्रशिक्षित	2017–18 में प्रशिक्षित	2018–19 में प्रशिक्षित	2019–20* में प्रशिक्षित	कुल प्रशिक्षित
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	100	0	0	0	0	0	0
2.	आन्ध्र प्रदेश	2000	235	398	211	464	488	1796
3.	अरुणाचल प्रदेश	200	30	0	0	0	0	30
4.	असम	2500	30	151	252	400	561	1394
5.	बिहार	2500	30	402	287	420	568	1707
6.	चंडीगढ़	100	0	0	58	90	90	238
7.	छत्तीसगढ़	2000	90	369	408	360	778	2005

8.	दादरा एवं नगर हवेली	10	0	0	0	0	0	0
9.	दमण एवं दीव	10	0	0	0	0	0	0
10.	दिल्ली	500	50	0	181	201	240	672
11.	गोवा	400	30	30	54	60	117	291
12.	गुजरात	2000	297	954	335	550	856	2992
13.	हरियाणा	1000	52	121	374	390	480	1417
14.	हिमाचल प्रदेश	500	0	36	138	150	120	444
15.	जम्मू एवं कश्मीर	700	26	0	60	158	306	550
16.	झारखण्ड	2000	0	152	185	180	269	786
17.	कर्नाटक	2500	90	420	513	348	363	1734
18.	केरल	2000	57	176	120	142	240	735
19.	लक्षद्वीप	100	0	0	30	0	0	30
20.	मध्य प्रदेश	4000	269	492	597	1164	1616	4138
21.	महाराष्ट्र	4000	660	829	561	883	1275	4208
22.	मणिपुर	500	30	30	30	60	0	150
23.	मेघालय	250	0	0	0	0	0	0
24.	मिजोरम	200	0	0	0	0	0	0
25.	नागालैंड	200	30	0	30	0	0	60
26.	ओडिशा	2500	0	931	268	567	511	2277
27.	पुडुचेरी	50	0	62	0	0	0	62
28.	पंजाब	2000	30	32	141	120	84	407
29.	राजस्थान	2500	53	581	597	775	1116	3122
30.	सिक्किम	200	0	0	0	0	0	0
31.	तमिलनाडु	2500	122	436	672	912	1132	3274
32.	तेलंगाना	2000	90	274	600	950	1401	3315
33.	त्रिपुरा	250	60	0	28	60	30	178
34.	उत्तर प्रदेश	5000	185	664	795	964	1604	4212
35.	उत्तराखण्ड	500	60	311	78	231	263	943
36.	पश्चिम बंगाल	2500	0	556	564	1313	1566	3999
	कुल	**50270**	**2606**	**8407**	**8167**	**11912**	**16074**	**47166**

*नोटः वित्त वर्ष 2019–20 की तीसरी और चौथी तिमाही में चलाए गए बैच समाप्त होने की रिपोर्ट नाइस से अभी प्राप्त नहीं हुई है।

11.3.5 सौर जल पंपिंगः मंत्रालय ने राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (नाइस), गुरुग्राम को वित्त वर्ष 2020–21 के लिए अखिल भारतीय आधार पर सौर जल पंपिंग प्रणालियों पर 900 वरुणमित्रों को प्रशिक्षित करने के लिए 30 प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मंजूरी दी है। नाइस द्वारा इन कार्यक्रमों का आयोजन विभिन्न भागीदार संस्थाओं जैसे कि सरकारी संस्थाएं, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेकनिक और अन्य संबद्ध संस्थाएं, जिन्हें लक्षित साझेदार के रूप में डिप्लोमा धारकों के साथ रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) द्वारा पैनल में शामिल किया गया है।

11.3.6 पवन ऊर्जा में कौशल विकास कार्यक्रम

वायुमित्र फाउंडेशन कोर्सः मंत्रालय ने वर्ष 2020–21 के लिए राष्ट्रीय पवन ऊर्ज संस्थान (नीवे) में 350 प्रशिक्षित कर्मियों के साथ वायुमित्र फाउंडेशन कोर्स नामक 10 लघु–कालिक (5 दिवसीय) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अनुमोदित

किये हैं, जो पवन विद्युत परियोजनाओं की स्थापना, प्रचालन और रखरखाव से संबंधित होंगे। इन 10 कार्यक्रमों में से, 5 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान (जीआरआई), डिंडिगुल, तमिलनाडु तथा 5 कार्यक्रमों का आयोजन नीवे में किया जाएगा। सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरे हो गए।

11.3.7 राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा इंटर्नशिप योजना (एनआरईआई)

मंत्रालय द्वारा नई योजना राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा इंटर्नशिप (द नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी इंटर्नशिप – एनआरईआई) के तहत इंटर्न के रूप में भारत या विदेश में मान्यता प्राप्त संस्थानों या विश्वविद्यालयों में नामांकित अंडर–ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या रिसर्च स्कॉलर का अध्ययन करने वाले छात्रों की सुविधा के लिए इंटर्नशिप का अवसर प्रदान किया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत वर्ष 2020–21 में एमटेक, बीटेक, एमएससी, और एमबीए छात्रों को 13 इंटर्नशिप प्रदान की गई और अन्य 10 इंटर्नशिप का प्रस्ताव है।

11.3.8 अन्य महत्वपूर्ण एचआरडी गतिविधियां और पहलः

क **आईटीआई में अक्षय ऊर्जा (आरई) पाठ्यक्रमः** आईटीआई में पवन ऊर्जा और लघु पन बिजली क्षेत्रों में आरई पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के तहत प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) के साथ समन्वय करके पवन ऊर्जा और एसएचपी में पाठ्यक्रम सामग्री को डिजाइन करने के लिए दो समितियों का गठन किया गया था।

ख **ऑनलाइन एचआरडी (मानव संसाधन विकास) पोर्टलः** मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 6 अक्टूबर, 2020 को एक ऑनलाइन पोर्टल (hrd.mnre.gov.in) की शुरुआत की गई, जिसमें आवेदन को ऑनलाइन प्रस्तुत करने, प्रसंस्करण और अन्य अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा फेलोशिप योजना और राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा इंटर्नशिप योजना की ऑनलाइन स्थिति की जाँच करने जैसी सेवाएं शामिल हैं।

ग **तीसरे री–इन्वेस्ट 2020 में भागीदारीः** तीसरे ग्लोबल आरई–इन्वेस्ट 2020 के एक भाग के रूप में दिनांक 27.11.2020 को स्किलिंग फॉर रिन्यूएबल्स फ्रॉम आईटीआई टू आईआईटी विषय पर एक तकनीकी सत्र आयोजित किया गया था। डॉ. वसंता वी. ठाकुर, वैज्ञानिक डी, एमएनआरई इस सत्र के लिए समन्वयक थीं और श्री के. कृष्णन, अध्यक्ष, कॉमनवेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स और प्रबंध निदेशक, स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स, मॉडरेटर थे। पैनल में सचिव, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, कॉमनवेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स से कौशल विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ), जिनेवा, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), बेरफुट कॉलेज इंटरनेशनल, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) रुडकी और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) जैसे महानुभाव शामिल थे। सत्र में तकनीशियन स्तर, पर्यवेक्षी स्तर के साथ–साथ अन्य विश्वविद्यालयों में प्रबंधकीय स्तर के पाठ्यक्रमों की आवश्यकता और अक्षय ऊर्जा में री–स्किलिंग और अप–स्किलिंग अल्पावधि पाठ्यक्रमों की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

27 नवंबर 2020 को आयोजित वुमेन इन रिन्यूएबल एनर्जी (अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में महिलाएं) पर सत्र का समन्वयन डॉ. वसंता वी. ठाकुर, एमएनआरई द्वारा किया गया और अन्य के साथ अक्षय ऊर्जा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन, परियोजना विकास के विभिन्न क्षेत्रों में वुमन एचीवर्स द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया। सत्र का प्रमुख कारण यह था कि एमएनआरई–उद्योग–सिविल सोसायटी–शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी को मजबूत करने के लिए अक्षय ऊर्जा के कार्य में महिलाओं को शामिल करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि अक्षय ऊर्जा कंपनियों के पास परामर्श देने के लिए ऐसे प्रायोजक और परामर्शदाता हों, जो महिलाओं को परामर्श, शिक्षित और पोषित कर सकें, ताकि वे नेतृत्व भूमिकाओं में प्रगति कर सकें। पैनल ने इस बात पर बल दिया कि सही पारिस्थितिकी तंत्र के साथ महिलाएं आवश्यक कौशल का चयन कर स्वयं को तैयार कर सकेंगी और अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में उभरते अवसरों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए आत्मविश्वास विकसित कर सकेंगी।

11.4 प्रशासन – ई–गवर्नन्स, सतर्कता, पुस्तकालय और सूचना का अधिकार

11.4.1 ई–गवर्नन्स और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) पहल

भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल में सहयोग के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पारदर्शिता लाने और हितधारकों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए विभिन्न वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप विकसित किए हैं।

एमएनआरई के वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप–ई–गवर्नन्स की ओर एक कदम

क **मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट (https://mnre.gov.in):** मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट को हितधारकों तक सूचनाओं के बेहतर प्रसार के लिए अपडेट और री–डिजाइन किया गया हैं। वैबसाइट पर सूचना हिंदी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं।

ख **स्पिन पोर्टल (https://solarrooftop.gov.in):**

इस पोर्टल का विकास सौर रूफटॉप परियोजनाओं की संस्थापना के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑनलाइन आवेदन और परियोजना समाप्ति रिपोर्टों को प्रस्तुत करने के लिए किया गया था। यह पोर्टल उमंग पोर्टल के साथ भी सिंक्रोनाइज्ड है।

ग **एचआरडी पोर्टल (https://hrd.mnre.gov.in):**

यह पोर्टल मंत्रालय के निम्नलिखित एचआरडी कार्यक्रमों के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए विकसित किया गया है:

- राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा इंटर्नशिप योजना,
- राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा फेलोशिप कार्यक्रम,
- राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा विज्ञान फेलोशिप कार्यक्रम,
- अक्षय ऊर्जा में अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम,

घ **सीसीडीसी सोलर (https://scms.gov.in/):**

यह पोर्टल नई सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए आवश्यक घटकों के आयात के लिए रियायती सीमा–शुल्क प्रमाणपत्र जारी करने के लिए है।

सौर ऊर्जा परियोजनाओं की शुरुआती स्थापना के लिए सामग्री के आयात के लिए सीमा शुल्क में छूट

वित्त मंत्रालय की दिनांक 6 जनवरी, 2011 की अधिसूचना संख्या 1/2011–सीमा शुल्क, दिनांक 6 जनवरी 2011; अधिसूचना (संशोधन) सं. 21/2011–सीमा शुल्क, दिनांक 17 मार्च 2012, अधिसूचना (संशोधन) सं. 14/2014–सीमा शुल्क, दिनांक 11 जुलाई, 2014 की अधिसूचना सं. 44–2017–सीमा शुल्क दिनांक 30 जून 2017 के संदर्भ में यह मंत्रालय सौर ऊर्जा परियोजनाओं की प्रारंभिक स्थापना के लिए आवश्यक वस्तुओं / सामग्रियों / घटकों के आयातों के लिए शुल्क रियायत प्राप्त करने के लिए रियायती सीमा शुल्क प्रमाण पत्र (सीसीडीसी) जारी करता था। वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, मंत्रालय ने 6156.49 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाओं के लिए सीसीडीसी जारी करने के लिए आवेदन स्वीकार किये थे। वित्त वर्ष 2020–21 के लिए बजट घोषणा को देखते हुए, जिसके बाद वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 1 फरवरी, 2021 की अधिसूचना सं. 7/2021–सीमा शुल्क के माध्यम से, दिनांक 6 जनवरी, 2011 की पूर्व अधिसूचना तथा अनुवर्ती संशोधनों को रदद् करते हुए, सीसीडीसी जारी करना बंद कर दिया गया है।

ड़ **सीसीडीसी पवन (https://ccdcwind.gov.in/):**

इसी प्रकार यह पोर्टल पवन टरबाइनों के विनिर्माण के लिए आवश्यक घटकों के आयात के लिए रियायती सीमा–शुल्क प्रमाणपत्र जारी करने के लिए है।

च **बायोऊर्जा पोर्टल (https://biourja.mnre.gov.in):**

यह निम्नलिखित योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए है:

» शहरी, औद्योगिक, कृषि अपशिष्ट/अवशिष्ट और नगरपालिका ठोस अपशिष्ट से ऊर्जा।

» देश में चीनी मिलों और अन्य उद्योगों में बायोमास–आधारित सह–उत्पादन को प्रोत्साहन।

छ **बायोगैस वेब पोर्टल (https://biogas.mnre.gov.in/):** यह पोर्टल नवीन राष्ट्रीय बायोगैस एवं जैव खाद कार्यक्रम (एनएनबीओएमपी) योजना के कार्यान्वयन के लिए है और यह मोबाइल ऐप प्लेटफॉर्म (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.biogas) पर भी उपलब्ध है।

ज **आर एंड डी पोर्टल (https://serviceonline.gov.in/dbt/):** यह अक्षय ऊर्जा से संबंधित अनुसंधान एवं विकास प्रस्तावों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए है।

झ **सोलर ऑफ–ग्रिड पोर्टल (https://solaroffgrid.mnre.gov.in/):** यह पोर्टल ऑफ ग्रिड और विकेन्द्रीकृत सौर पीवी अनुप्रयोगों की स्थापना के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रस्तावों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए विकसित किया गया था।

ञ **पीएम कुसुम पोर्टल (http://pmkusum.mnre.gov.in/landing.html):** यह पोर्टल किसानों हेतु बनाई गई पीएम कुसुम योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए विकसित किया गया था।

ट **सोलर स्ट्रीट लाइट पोर्टल (https://ssl.mnre.gov.in/):** यह सौर स्ट्रीट लाइट की स्थापना की निगरानी के लिए विकसित किया गया था जो मोबाइल ऐप (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mnre.streetlightingapp) के माध्यम से भी उपलब्ध है।

ठ **इनवेस्टमेंट पोर्टल (https://investment.mnre.gov.in/):** यह पोर्टल आरई डेवलपर्स की शिकायतों को दूर करने के लिए उद्योग और निवेशकों को एक ही स्थान पर सहायता और सुविधा प्रदान करने के लिए है।

ड **अक्षय ऊर्जा पोर्टल (https://akshayurja-gov-in):** यह पोर्टल अक्षय ऊर्जा की उपलब्ध समग्र क्षमता, ग्रिड संबद्ध और ऑफ ग्रिड सहित प्रत्येक ऊर्जा के लिए उपलब्ध कुल क्षमता वर्धन और मासिक उत्पादन के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ये आंकड़े राज्य–वार उपलब्ध हैं।

ढ **आईआरआईएक्स (भारतीय अक्षय ऊर्जा विचारों का आदान–प्रदान) पोर्टल (https://irix.gov.in) :** आईआरआईएक्स, नवीकरणीय ऊर्जा पर विचारों का आदान–प्रदान करने और उत्प्रेरित करने के लिए एक बहु–हितधारक सहयोगी मंच है।

ण **ईएचआरएमएस:** ई–एचआरएमएस, कार्मिक प्रबंधन गतिविधियों जैसे छुट्टी, पोस्टिंग, पदोन्नति, स्थानांतरण, सेवा पुस्तिका के रखरखाव आदि के लिए एक सामान्य एप्लिकेशन टूल है।

त **ई–ऑफिस:** मंत्रालय ने ई–ऑफिस को पूरी तरह से लागू कर दिया है, जो फाइलों और प्राप्तियों/पत्रों को प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने और ऑनलाइन संचलन के लिए है। ई–ऑफिस की प्रभावकारिता और उपयोगिता विशेष रूप से लॉकडाउन समय के दौरान दिखाई दी थी, जब 'वर्क फ्राम होम' अवधियों के दौरान भी मंत्रालय का काम बिना किसी व्यवधान के जारी रहा।

11.4.2 सतर्कता

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के सतर्कता प्रभाग को भारत सरकार और केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी विभिन्न नियमों, दिशानिर्देशों और अनुदेशों के अनुसार भ्रष्टाचार निरोधक उपाय करने का दायित्व सौंपा गया है। मंत्रालय का सतर्कता एकक मंत्रालय और इसके तीन स्वायत्त निकायों, नामतः राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (नाइस), राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (नीवे) और राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान (नीबे) के सतर्कता कार्यों की देखरेख करता है। इस प्रभाग को मंत्रालय के अधिकारियों की वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) और अचल संपत्ति विवरणी (आईपीआर) के रखरखाव का दायित्व सौंपा गया है।

वर्ष 2020 के दौरान सतर्कता प्रभाग में प्राप्त शिकायतों की नियमों आदि दिशानिर्देशों के अनुसार जांच की गई और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई की गई।

मंत्रालय में दिनांक 27 अक्तूबर, 2020 से 02 नवम्बर, 2020 तक सतर्कता जागरुकता सप्ताह मनाया गया और निम्नलिखित कार्यकलाप किए गए:–

» सभी कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा सत्यनिष्ठा की शपथ ली गई।

» निवारक सतर्कता पर व्याख्यान का आयोजन किया गया।

» मंत्रालय के अधिकारियों के लिए निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई।

» मंत्रालय के परिसर में भ्रष्टाचार निवारण और निवारक सतर्कता पर स्लोगन व बैनर लगाए गए।

» सतर्कता मामलों पर पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

इस मंत्रालय और इसके स्वायत्त संगठनों के संबंध में सत्यनिष्ठा संबंधी मामले अपलोड किए गए और बोर्ड स्तर के अधिकारियों के संबंध में सतर्कता संबंधी जानकारी को ई–पोर्टल सॉल्व (एसओएलवीई) पर मासिक रूप से अद्यतित किया जाता है। इस मंत्रालय के अधिकारियों की नियमानुसार 56(जे) के तहत लगातार समीक्षा भी की जाती है।

11.4.3 पुस्तकालय

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का पुस्तकालय अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में संदर्भ केन्द्र और ज्ञान भंडार के रूप में कार्य करता है। वर्तमान में पुस्तकालय में लगभग 15,527 पुस्तकें (उपहार में प्राप्त पुस्तकों सहित) उपलब्ध हैं जिनमें अक्षय ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक विज्ञान, धारणीय विकास, इतिहास, समाजशास्त्र, भारतीय साहित्य, कंप्यूटर विज्ञान आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों की पुस्तकें शामिल हैं। पुस्तकालय के संग्रह में आम रुचि की पुस्तकें जैसे – खाद्य पदार्थ, रसोई, मूर्ति कला, पेंटिंग, पर्वतारोहण आदि भी शामिल हैं।

» मंत्रालय में गठित पुस्तकालय समिति पुस्तकों की संवीक्षा करती है और पुस्तकालय द्वारा खरीद हेतु इनकी संस्तुति करती है।

» वर्तमान में पुस्तकालय द्वारा हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में 40 पाक्षिक पत्रिकाएं खरीदी जा रही हैं। इसके अतिरिक्त पुस्तकालय द्वारा आवश्यकतानुसार हिन्दी और अंग्रेजी में कुल 23 समाचार पत्र भी खरीदे जा रहे हैं। पुस्तकालय क्लाउड आधारित सॉफ्टवेयर ई–ग्रंथालय वर्जन 4.0 का उपयोग कर रहा है।

11.4.4 सूचना का अधिकार अधिनियम

मंत्रालय द्वारा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), केन्द्रीय सूचना आयोग और गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन किया जा रहा है। आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करने संबंधी प्रक्रिया/अन्य विवरण एमएनआरई वेबसाइट www.mnre.gov.in पर उपलब्ध है।

दिनांक 01.01.2020 – 31.12.2020 तक की अवधि के दौरान प्राप्त किए गए, निपटाए गए तथा लंबित आरटीआई आवेदनों/प्रथम अपीलों से संबंधित प्रगति रिपोर्ट **तालिका–11.3** में दी गई है।

तालिका 11.3 : दिनांक 01.01.2020 से 31.12.2020 तक की अवधि के दौरान प्राप्त किए गए, निपटाए गए तथा लंबित आरटीआई आवेदन/प्रथम अपील

सामग्री	प्राप्त	निपटान किया गया	31.12.2020 की स्थिति के अनुसार लंबित
आरटीआई आवेदनों	554	511	43
प्रथम अपीलें	80	71	09

मंत्रालय ने आवंटित किए गए विषय के अनुसार आरटीआई आवेदनों और प्रथम अपील का उत्तर देने के लिए केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और प्रथम अपील अधिकारी (एफएएए) नियुक्त किए हैं। सीपीआईओ और प्रथम अपील अधिकारियों की सूची **तालिका–11.4** में दी गई है। सुश्री अलका जोशी, उप सचिव की अगुवाई में मंत्रालय का आरटीआई एकक सभी भौतिक और ऑनलाइन आवेदनों का समन्वयन करता है और केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों और प्रथम अपील अधिकारियों को निर्धारित समयावधि के भीतर उनका उत्तर देने के लिए अग्रेषित करता है।

तालिका–4 : कार्य के पुनरावंटन के आधार पर नामित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) और अपील अधिकारियों की सूची (31.12.2020 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	विषय	सीपीआईओ	अपील अधिकारी
1.	स्वच्छ विकास तंत्र (सीडीएम) सहित जलवायु परिवर्तन संबंधी पहलें, नियामक अनुपालना निदेशालय, आरईसी नीति, री–इन्वेस्ट संबंधी दस्तावेज, आईएसए, एनसीईएफ, नई प्रौद्योगिकियाँ, हाइड्रोजन ईंधन सेल, हरित जलवायु कोष परियोजनाएं और एमओईएफ एवं सीसी तथा नाबार्ड, नेशनल बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक मोबाइलिटी (एनबीईएम) के साथ समन्वयन।	श्री दीपेश फेरवानी, वैज्ञानिक 'सी'	डॉ. पी.सी. मैथानी, वैज्ञानिक 'जी'
2.	मासिक पुनः प्रगति डाटा संकलन और अद्यतन, मासिक कैबिनेट अर्धशासकीय पत्र बनाना, मंत्री जी की बैठकों हेतु संक्षिप्त नोट तैयार करना, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन संबंधी सभी मामले।	श्री अनुभव उप्पल, वैज्ञानिक 'सी'	डॉ. पंकज सक्सेना वैज्ञानिक 'जी'

3.	ईएफसी / कैबिनेट/पावर नोट्स / कान्सैप्ट पेपर पर अन्य मंत्रालयों से प्राप्त टिप्पणियाँ। बैक ग्राउंड नोट तैयार करना। स्थायी समिति की बैठकों के लिए पीपीटी निर्माण / ऊर्जा मंत्री संगोष्ठी / आरपीएम बैठक / अन्य समीक्षा बैठक इत्यादि। माननीय मंत्रीजी के स्वतंत्रता दिवस के भाषण के इनपुट तैयार करना/ माननीय वित्त मंत्री का बजट भाषण तैयार करना, विजन डॉक्यूमेंट की सिफारिशों पर पूर्वोत्तर क्षेत्र की एटीआर सहित वार्षिक रिपोर्ट हेतु अध्याय का संक्षिप्त लेखन, पीआईबी इनपुट के लिए वर्ष की समाप्ती की समीक्षा। वार्षिक पीएम अवसंरचना खंड समीक्षा एवं आउट पुट मोनिट्रिंग फ्रेम (ओओएमई) सहित नीति आयोग से संबन्धित सभी मामले। बजट घोषणा के अपडेट सहित ई–समीक्षा पोर्टल और अन्य पोर्टलों को नियमित अपडेट करना। अन्य विविध कार्य।	श्री विपिन कुमार, उप निदेशक	श्री जे. राजेश कुमार, आर्थिक सलाहकार
4.	हरित ऊर्जा कॉरिडोर, भूतापीय, सागरीय/ज्वारीय ऊर्जा	श्री रोहित ठकवानी वैज्ञानिक 'सी'	श्री गिरीश कुमार वैज्ञानिक 'ई'
5.	सूचना प्रौद्योगिकी, आरई–पोर्टल प्रयोगशाला नीति, मानक और गुणवत्ता नियंत्रण का विकास	श्री विक्रम ढाका, वैज्ञानिक 'सी'	श्री अरूण कुमार, निदेशक
6.	लद्दाख में पीएमपीडी के अंतर्गत सौर परियोजनाएं, पूर्वोत्तर राज्यों, झारखंड और ओडिशा में सौर पार्क, अन्य सीपीएसयू द्वारा यूएमआरईपीपी	श्री अरविंद एमए, वैज्ञानिक 'सी"	श्री सुनील कुमार गुप्ता,वैज्ञानिक 'डी'
7.	वीजीएफ योजना, रूफटोप पीवी और लघु सौर विद्युत उत्पादन कार्यक्रम (आरपीएसएसजीपी), जीबीआई योजना, सौर शहर और ग्रीन बिल्डिंग, एनटीपीसी–बंडलिंग, एनटीपीसी–ईपीसी परियोजनाएं, कोणार्क योजना/वाणिज्य विभाग से संबन्धित मामले।	श्री अरविंद एमए, वैज्ञानिक 'सी"	श्री गिरीश कुमार, वैज्ञानिक 'ई'
8.	बायोमास विद्युत योजनाएं और नीतियां, जैव ऊर्जा मिशन, बायोमास कुक स्टोव, बायोमास गैसीफायर और जैव ऊर्जा संबंधी विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं से जुड़े सभी कार्य	सुश्री प्रिया, वैज्ञानिक 'सी'	श्री असीम कुमार, निदेशक
9.	अपशिष्ट से ऊर्जा	श्री विजय कुमार भारती, वैज्ञानिक 'सी'	श्री असीम कुमार, निदेशक
10.	बायो गैस विद्युत (ऑफ ग्रिड कार्यक्रम), बायो गैस प्रशिक्षण केंद्र और बायोमास आर एंड डी	श्री एस.आर. मीणा, वैज्ञानिक 'सी'	श्री दिनेश दयानन्द जगदले, संयुक्त सचिव
11.	इरेडा, सेकी के सभी प्रशासनिक मामले	श्री अरविंद सहदेव घोलप, अनुभाग अधिकारी	श्री संजय कर्णधार, वैज्ञानिक 'डी'

12.	ऑफ–ग्रिड सौर, कृषि पंप योजना, स्ट्रीट लाइट, होम लाइट, एसएडीपी, अक्षय उर्जा शॉप, कुसुम कार्यक्रम	श्री शोभित श्रीवास्तव वैज्ञानिक 'डी'	श्री जीवन कुमार जेठानी, वैज्ञानिक 'ई'
13.	एचआरडी एंड आईटीईसी	डॉ वसन्ता वी ठाकुर वैज्ञानिक 'डी'	श्री जी. उपाध्याय, वैज्ञानिक 'जी'
14	ऊर्जा भंडारण, भूतल परिवहन के लिए बिजली चालित वाहन, अक्षय ऊर्जा पत्रिका, मीडिया पॉलिसी, स्टोरेज, बैटरी टेस्टिंग (आर एंड डी), ईएफएम	श्री तरुण सिंह वैज्ञानिक 'डी'	डॉ. पी.सी. मैथानी, वैज्ञानिक 'जी'
15	रूफटॉप सोलर, प्रत्येक राज्य में एक सौर शहर, जिनमें घरों का 100 प्रतिशत सोलरीकरण	श्री मनीष सिंह बिस्ट, वैज्ञानिक 'सी'	श्री हिरेन बोराह, वैज्ञानिक 'डी'
16	पवन ऊर्जा (तटीय), पवन ऊर्जा (अपतटीय), लघु पवन, लघु पवन, आर एवं डी (पवन)	श्री पी.के. दाश वैज्ञानिक 'डी'	श्री भानु प्रताप यादव, संयुक्त सचिव
17	आर एंड डी समन्वय और निगरानी	श्री किशोर कुमार, उप निदेशक	श्री अनिल कुमार, वैज्ञानिक 'डी'
18	दिशानिर्देश और मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी), सीपीएसयू सरकारी उत्पादक योजना, नहरों के ऊपर सौर योजना, जीएसटी सेल, सौर उत्पादक योजना, एफडीआई सेल, अक्षय ऊर्जा उद्योग संवर्धन और सुविधा बोर्ड	श्री संजय कर्णधार, वैज्ञानिक 'डी'	श्री रुचिन गुप्ता, निदेशक
19	द्वीपों की हरियाली	श्री संजय कर्णधार, वैज्ञानिक 'डी'	श्री भानु प्रताप यादव, संयुक्त सचिव
20	री–इन्वेस्ट का आयोजन, लघु पन बिजली परियोजनाएं	श्री एस. के. साही, वैज्ञानिक 'डी'	श्री भानु प्रताप यादव, संयुक्त सचिव
21	डीबीटी सेल	श्री अरुण कुमार, वैज्ञानिक 'डी'	श्री भानु प्रताप यादव, संयुक्त सचिव
22	सौर ऊर्जा विद्युत परियोजनाओं के लिए सीसीडीसी	श्री अरुण कुमार, वैज्ञानिक 'डी'	श्री बी.के. पांडा, वैज्ञानिक 'ई'
23	बायोगैस से संबंधित जी.एस.टी.	श्री एस.आर. मीणा, वैज्ञानिक 'डी'	श्री रुचिन गुप्ता, निदेशक
24	पवन सीडीसी/ईडीई से संबंधित जीएसटी	श्री एस.के. खुराना, अवर सचिव	श्री रुचिन गुप्ता, निदेशक
25	सौर सीडीसी/ईडीई से संबंधित जीएसटी	श्री अरुण कुमार, वैज्ञानिक 'डी'	श्री रुचिन गुप्ता, निदेशक
26	ऑफ ग्रिड सोलर से संबंधित जीएसटी	श्री शोभित श्रीवास्तव, वैज्ञानिक 'डी'	श्री रुचिन गुप्ता, निदेशक
27	बायोमास से संबंधित जीएसटी	सुश्री प्रिया, वैज्ञानिक 'सी'	श्री रुचिन गुप्ता, निदेशक
28	पवन ऊर्जा के लिए सीसीडीसी	श्री एस.के. खुराना, अवर सचिव	श्री बी.के. पांडा, वैज्ञानिक 'ई'
29	आई एंड पीए और सेमिनार तथा संगोष्ठी	श्री ए.के. मनीष, अवर सचिव	श्री एन.बी. राजू, वैज्ञानिक 'ई'

30	सतर्कता	सुश्री सुनीता धेवाल, अवर सचिव	श्री के. सलिल कुमार, उप सचिव
31	राष्ट्रीय सौर मिशन, सौर पार्क, रक्षा योजनाएँ	श्री देवेन्द्र सिंह, अवर सचिव	श्री दिलीप निगम, वैज्ञानिक 'जी'
32	अंतर्राष्ट्रीय संबंध (आईआर)	श्री चलपति राव, वैज्ञानिक 'सी'	श्री असीम कुमार, निदेशक
33	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), का कार्यालय	श्री डी.के. पांडे, अवर सचिव	श्री भानु प्रताप यादव, संयुक्त सचिव
34	विधायी प्रकोष्ठ	श्री ए.के. सिंह, अवर सचिव	श्री के. सलिल कुमार, उप सचिव
35	संसदीय कार्य	श्री ए. के. सिंह, अवर सचिव	डॉ. पंकज सक्सेना, वैज्ञानिक 'जी'
36	जनता की शिकायतें	श्री ए.के. सिंह, अवर सचिव	सुश्री अलका जोशी, उप सचिव
37	प्रशासन	श्री अरविंद पोखरियाल, अवर सचिव	श्री के. सलिल कुमार, उप सचिव
38	एसएसएस–नीबे के सभी मामले	श्री योगिंदर सिंह, अवर सचिव	श्री असीम कुमार, निदेशक
39	आईएफडी	श्री के.जी. सुरेश कुमार, अवर सचिव	श्री संदीप मुखर्जी, उप सचिव
40	आरटीआई मामले, लाइब्रेरी, बजट, व्यय की निगरानी, लेखा परीक्षा और सांख्यिकीय विश्लेषण	सुश्री सुनीता सजवान, अवर सचिव	सुश्री अलका जोशी, उप सचिव
41	रोकड़ अनुभाग	सुश्री सुनीता सजवान, अवर सचिव	श्री के. सलिल कुमार, उप सचिव
42	हिन्दी	श्री नन्दन सिंह दुग्ताल, उप निदेशक (रा.भा.)	सुश्री अलका जोशी, उप सचिव
43	पीएओ, बजट	श्री प्रताप सिंह, वरिष्ठ लेखा अधिकारी	श्री अरविंद कुमार, प्रमुख लेखा नियंत्रक
44	नाइस के सभी प्रशासनिक और वित्तीय मामले	श्री देवेन्द्र सिंह, अवर सचिव	श्री के. सलिल कुमार, उप सचिव
45	नीवे के सभी प्रशासनिक और वित्तीय मामले	श्री राहुल रावत, वैज्ञानिक 'सी'	श्री के. सलिल कुमार, उप सचिव

अध्याय

12

अक्षय ऊर्जा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

अक्षय ऊर्जा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

12.1 मंत्रालय का अंतर्राष्ट्रीय संबंध (आईआर) प्रभाग, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग, विकास और स्थापना के लिए तथा समझौता ज्ञापन (एमओयू) और करार पर हस्ताक्षर करने के लिए अन्यों के साथ–साथ आर्थिक कार्य विभाग (डीईए), विदेश मंत्रालय (एमईए), विभिन्न देशों में स्थित भारतीय मिशन, भारत में स्थित विभिन्न देशों के दूतावास, बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ लगातार कार्य कर रहा है।

12.2 वर्तमान वर्ष के दौरान भी मंत्रालय ने अधिकतर वर्चुअल मोड के माध्यम से द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और संयुक्त कार्य समूह (जेडबल्यूजी) बैठकें आयोजित करके समझौता ज्ञापन, कार्यान्वयन समझौते (आईए) पर हस्ताक्षर करके नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें की हैं। शिष्टमंडल का नेतृत्व अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में इन कार्यक्रमों के लिए माननीय मंत्री और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर किया गया।

12.3 एमएनआरई ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विभिन्न देशों और संगठनों के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) और करारों पर हस्ताक्षर किए हैं। हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के तहत संयुक्त कार्य समूह (जेडबल्यूजी) का गठन, कार्यान्वयन के लिए संयुक्त गतिविधियों की पहचान करने, चयन करने और निर्माण करने के लिए किया गया। विदेश मंत्रालय (एमईए), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी), वाणिज्य और ऊद्योग मंत्रालय (एमओसीएंडआई), विद्युत मंत्रालय (एमओपी), नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांन्सर्फोमिंग इंडिया (नीति) आयोग जैसे अन्य मंत्रालयों द्वारा स्थापित संयुक्त कमीशन बैठकों (जेसीएम), संयुक्त कार्य समूह (जेडब्लूजी) बैठकों, संयुक्त व्यपार समितियों (जेटीसी) बैठक के माध्यम से विभिन्न देशों के साथ बातचीत की जा रही है। सहयोग के लिए पारस्परिक रूप से सहमत परियोजनाओं और कार्यों की स्थापना भी विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय स्तर पर की गई, हालांकि उनके साथ कोई विशिष्ट समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

12.4 इसके अलावा, एमएनआरई द्वारा अन्यों के साथ–साथ एसोसियेशन ऑफ साउथ–इस्ट एशियन नेशंस (आसियान), बे ऑफ बेंगाल इनिशियेटिव फॉर मल्टी–सेक्टोरल टेकनीकल एंड इकनॉमिक कोओपरेशन (बीम्सटेक), ब्राजील–रशिया–इंडिया–चाइना–साउथ अफ्रीका (ब्रिक्स), कोलंबो प्लान, जी–20, इंडिया–ब्राजील–साउथ अफ्रीका (आईबीएसए), इंडियन ओशियन रिम एशोसियेशन (आईओआरए), साउथ एशियन एशोशियेशन फॉर रीजनल कोओपरेशन (सार्क), साउथ एशिया सब–रीजनल इकोनोमिक कोओपरेशन (सासेक) और शांघाइ कोओपरेशन ओर्गेनाइजेशन (एससीओ) जैसे विभिन्न बहुपक्षीय सहयोग ढ़ांचे के तहत सहयोग किया जा रहा है।

12.5 मंत्रालय अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के बारे में तकनीकी जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए अन्यों के साथ–साथ एशियाई विकास बैंक (एडीबी), एजेंसी फ्रांकेइस डि डेवलपमेंट (एएफडी), डेनिश एनर्जी एजेंसी (डीईए), टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क (डीटीयू), यूरोपीय संघ (ईयू), फोरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस (एफसीडीओ), डायचे गेसल्सचफ्ट फर इंटरनेशनल जुसमेनरबीट (जीआईजेड़), इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी (इरेना), इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (आईईए), अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए), क्रिडेस्तानस्टाल्ट फ्यूर वाडेराफ्यूबाऊ (केएफडबल्यू), फिजिकलिश्च–टेक्निश्चे बनडेशानस्टॉल (पीटीबी), यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएड), यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम (यूएनडीपी), यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (यूनिडो), वर्ल्ड बैंक (विश्व बैंक) जैसी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और एजेंसियों के साथ कार्य करता है।

12.6 मंत्रालय, भारत सरकार के इंडियन टेक्निकल एंड इकोनोमिक कॉर्पोरेशन (आईटीईसी) कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (नाइस), गुरुग्राम, राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (नीवे), चेन्नई, वैकल्पिक हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेंटर (एएचईसी), आईआईटी, रुडकी जैसे प्रमुख संस्थानों के माध्यम से विकासशील और कम विकासशील देशों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भारत में लघु पन बिजली और बायोमास के क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन की व्यवस्था भी करता है।

12.7 वर्तमान वर्ष के दौरान, निम्नलिखित समझौता ज्ञापन और सहयोग करार पर हस्ताक्षर किए गए:–

» "एक–सूर्य–एक–विश्व–एक ग्रिड (ओसोवोग) पहल के कार्यान्वयन" के संबंध में दिनांक 08.09.2020 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए), नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलमेंट और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोशियेशन के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

» सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए दिनांक 10.12.2020 को राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (नाइस), नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार तथा इंटरनेशनल सोलर एनर्जी इंस्टीट्यूट (आईएसईआई), उज्बेकिस्तान सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

» अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए मिनिस्ट्री फॉर द इकोलॉजिकल ट्रान्जिशन ऑफ द फ्रेंच रिपब्लिक और भारत गणराज्य के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर नई दिल्ली में दिनांक 28.01.2021 को हस्ताक्षर किए गए।

12.8 वर्तमान वर्ष के दौरान, अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में निम्नलिखित संयुक्त कार्य समूह (जेडबल्यूजी) की बैठकों का आयोजन किया गया (**तालिका–12.1**):–

तालिका–12.1 : एमएनआरई द्वारा आयोजित संयुक्त कार्य समूह की बैठकें

क्र.सं.	देशों के बीच	बैठकों की तिथि	अभ्युक्तियां
1	भारत गणराज्य की सरकार का नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री ऑफ द रिपब्लिक ऑफ आइसलैंड	28 अगस्त, 2020	वर्चुअल रूप से आयोजित
2	भारत गणराज्य की सरकार का नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और द मिनिस्ट्री ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रान्सपोर्ट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ फिजी	10 सितम्बर, 2020	वर्चुअल रूप से आयोजित
3	भारत गणराज्य की सरकार और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटन तथा नोर्दन आयरलैंड की सरकार	18 सितम्बर, 2020	वर्चुअल रूप से आयोजित
4	भारत गणराज्य की सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और संयुक्त अरब अमीरात की सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ फोरेन अफेयर्स, डीईसीसी	11 नवम्बर, 2020	वर्चुअल रूप से आयोजित
5	भारत गणराज्य की सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और यूरोपीय संघ	13 नवम्बर, 2020	वर्चुअल रूप से आयोजित
6	भारत गणराज्य की सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और द मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड माइनिंग ऑफ द रिपब्लिक ऑफ पेरु	11 दिसम्बर, 2020	वर्चुअल रूप से आयोजित
7	भारत गणराज्य की सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ द गवर्नमेन्ट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ म्यांमार	18 दिसम्बर, 2020	वर्चुअल रूप से आयोजित
8	भारत गणराज्य की सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वॉटर अथोरिटी ऑफ गवर्नमेन्ट ऑफ किंग्डम ऑफ बहरीन	04 फरवरी, 2021	वर्चुअल रूप से आयोजित

उक्त के अलावा, एमएनआरई के तकनीकी सहायता कार्यक्रमों के अंतर्गत द्विपक्षीय/बहुपक्षीय एजेंसियों के साथ विभिन्न बैठकों, तथा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों आदि का कोविड–19 महामारी के दौरान भी वर्चुअल रूप से आयोजन किया गया।

12.9 तीसरे ग्लोबल रि–इन्वेस्ट मीट एंड एक्सपो का आयोजन दिनांक 26 से 28 नवम्बर 2020 के बीच वर्चुअल प्लैटफॉर्म पर किया गया। 27–28 नवम्बर 2020 के दौरान ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, मालदीव, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ तथा संयुक्त राष्ट्र अमरीका की एजेंसियों जैसे नौ देशों के सत्र आयोजित किए गए। ये सत्र बेहद लाभकारी थे जिनमें देश विशिष्ट की रुचि वाले क्षेत्रों और प्रौद्योगिकियों को शामिल किया गया।

12.10 द साऊथ एशियन ग्रुप फॉर एनर्जी (एसएजीई), मंत्रालय की संस्थाओं जैसे कि राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (नीवे), राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (नाइस) और राष्ट्रीय बायोमास ऊर्जा संस्थान (नीबे) तथा अमरीका की तीन राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं जैसे कि लोरेंस बर्कली नेशनल लेबोरेटरी (एलबीएनएल), द नेशनल रिन्युएबल एनर्जी लेबोरेटरी (एनआरईएल) और द पेसिफिक नार्थ–वेस्ट नेशनल लेबोरेटरी (पीएनएनएल) के बीच सहयोग के लिए एक संघ है। एसएजीई की शुरुआत एमएनआरई तथा यूएसएड द्वारा दिनांक 7 जुलाई 2020 को संयुक्त रूप से की गई। कई प्रमुख क्षेत्रों, जो इस सहयोग के प्रभाव को बढ़ाने में मदद करेंगे, की प्रतिभागी संस्थाओं द्वारा पहचान की गई है।

12.11 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पवन, हाईड्रोजन और सौर फोटोवोल्टेक्स के क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आइईए) के प्रौद्योगिकी सहयोग कार्यक्रमों (टीसीपीएस) में हिस्सा लेने की सहमति जताई है।

12.12 ऊर्जा पर संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय वार्ता के "एनर्जी ट्रांजिशन" विषयक विषय के लिए भारत को ग्लोबल चैंपियन घोषित किया गया है। एमएनआरई सितंबर 2021 में निर्धारित कार्यक्रम के लिए विषय का नेतृत्व करेगा।

चित्रः 12.1 दिनांक 28.01.2021 को नई दिल्ली में मिनिस्ट्री फॉर द इकोलॉजिकल ट्रांजिशन ऑफ द फ्रेंच रिपब्लिक तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के बीच अक्षय ऊर्जा सहयोग पर हस्ताक्षर किए गए।

12.13 अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी (इरेना) के साथ कार्य

12.13.1 इरेना एक अंतर–सरकारी संगठन है जो एक सतत भावी ऊर्जा के लिए देशों को उनके बदलाव में सहयोग करता है और अक्षय ऊर्जा पर नीति, प्रौद्योगिकी, संसाधन तथा वित्तीय जानकारी के भंडार तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक प्रमुख मंच, उत्कृष्टता के केन्द्र के रूप में कार्य करता है और भारत, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी (इरेना) का एक संस्थापक सदस्य है। इरेना द्वारा सतत विकास, उर्जा पहुंच, ऊर्जा सुरक्षा और अल्प कार्बन आर्थिक विकास और समृद्धि की खोज में जैव–उर्जा, भू–तापीय, हाइड्रो विद्युत, महासागर, सौर तथा पवन ऊर्जा सहित अक्षय ऊर्जा के सभी प्रकारों को व्यापक रूप से अपनाने और इसके सतत उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है।

12.13.2 इरेना द्वारा सरकारों को अक्षय ऊर्जा निवेश के लिए सामर्थ्यकारी नीतियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, अक्षय ऊर्जा की तैनाती में तेजी लाने के लिए व्यावहारिक उपकरण और नीति संबंधी सलाह प्रदान की जाती

है और विश्व की बढ़ती जनसंख्या के लिए स्वच्छ, सतत ऊर्जा प्रदान करने के लिए ज्ञान को साझा करने तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की जाती है। भारत द्वारा इरेना की परिषदीय बैठकों और आम सभा में नियमित रूप से हिस्सा लिया जाता है और सकारात्मक सुझाव दिये जाते हैं। भारत, वर्ष 2021 के दौरान इरेना की सभा के उपाध्यक्ष के रूप में भी भाग लेगा।

12.13.3 इरेना के 11वें सत्र की आम सभा का वर्चुअल आयोजन दिनांक 18 से 21 जनवरी 2021 के दौरान अबु धाबी में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किया गया। ग्यारहवीं इरेना सभा में 330 संगठनों से 134 सदस्यों और प्रतिनिधि सहित, 144 देशों से 2100 से अधिक पंजीकृत प्रतिभागियों ते भाग लिया। भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व माननीय विद्युत एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने किया तथा सचिव और संयुक्त सचिव (आईआर) ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। भारत को इरेना 2021 की सभा के 11वें सत्र के लिए नामित उपाध्यक्षों में शामिल किया गया।

माननीय विद्युत एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने दिनांक 20 जनवरी, 2021 को आयोजित "एनर्जी ट्रांजिशन फॉर सस्टेनेबल पोस्ट–कोविड रिकवरी" की उच्च स्तरीय पैनल बैठक में भाग लिया। माननीय मंत्री ने दिनांक 20 जनवरी, 2021 को आयोजित "रिन्यूएबल्स एडं पायवे टू कार्बन न्यूट्रालिटी–इनोवेशन, ग्रीन हाइड्रोजन एडं सोशियो–इकनॉमिक पॉलिसीज" सत्र की अध्यक्षता भी की।

सचिव एमएनआरई ने दिनांक 19 जनवरी, 2021 को आयोजित मेंबर इंटरवेंशन सत्र की अध्यक्षता की और दिनांक 19 जनवरी, 2021 को आयोजित मंत्रालयी प्लेनरी सत्र "नेशनल एनर्जी प्लानिंग एडं इंप्लिमेन्टेशन फॉर फॉस्टरिंग एनर्जी ट्रांजिशन" में वक्ता के रूप में भाग लिया। संयुक्त सचिव (आईआर) एमएनआरई ने दिनांक 19 जनवरी, 2021 को आयोजित" स्केलिंग अप फाइनेंस फॉर रिन्यूएबल्स" के मंत्रालयी प्लेनरी सत्र में भाग लिया।

12.14 अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन

12.14.1 इन्टरनेशनल सोलर अलायंस (आईएसए), जिसकी शुरुआत नवम्बर 2015 में की गई, यह सौर ऊर्जा को बढ़ाने के लिए प्रमुख आम चुनौतियों का सामूहिक रूप से समाधान करने की भारतीय पहल का परिणाम है। 15 देशों द्वारा आईएसए फ्रेमवर्क समझौते पर दिनांक 6 दिसम्बर 2017 को हस्ताक्षर और समर्थन के साथ, आईएसए भारत में मुख्यालय वाला प्रथम अंतर्राष्ट्रीय अंतर–सरकारी संगठन बना। दिनांक 3 अक्तूबर 2018 को आयोजित आईएसए की प्रथम सभा में संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के सभी सदस्य देशों के लिए आईएसए की सदस्यता के दायरे का विस्तार करने के लिए फ्रेमवर्क समझौते में संशोधन हेतु एक प्रस्ताव को अपनाया गया। वर्तमान तिथि के अनुसार, 88 देशों ने आईएसए के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें से 70 देशों ने इसका समर्थन भी किया है।

12.14.2 आईएसए ने दिनांक 8 सितम्बर 2020 को विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन आयोजित किया जिसका उद्घाटन भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने किया। **149 देशों** से 26,000 से अधिक प्रतिभागियों ने शिखर सम्मेलन में वर्चुअल रूप से हिस्सा लिया। वर्ष के दौरान, आईएसए की स्थायी समिति की बैठक का आयोजन अध्यक्ष, आईएसए तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत मंत्री की अध्यक्षता में दो बार किया गया और अंतिम बैठक का आयोजन दिनांक 10 सितम्बर, 2020 को किया गया। इसके अलावा, आईएसए की तीसरी सभा का आयोजन दिनांक 14 अक्तूबर, 2020 को किया गया।

12.14.3 आईएस ने अभी तक सात कार्यक्रमों की शुरुआत की हैः कृषि उपयोग के लिए सौर अनुप्रयोगों को बढ़ाना; स्केल पर वहनीय वित्त–पोषण; बड़ी–स्तर की ग्रिड संबद्ध सौर परियोजनाओं का विकास; सौर लघु–ग्रिडों का स्केलिंग; सौर रूफटॉप स्केलिंग और सौर ई–मोबिलिटी स्केलिंग तथा भंडारण; और तापीय तथा शीतलन प्रणाली का सौरीकरण। ये कार्यक्रम आईएसए सदस्य देशों में सार्वभौमिक ऊर्जा पहुंच और आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए सौर ऊर्जा तैनाती के समग्र लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होंगे।

12.14.4 अन्य के साथ–साथ विश्व बैंक, यूएनडीपी, यूरोपिय इन्वेस्टमैंट बैंक, ग्रीन क्लाइमेट फंड जैसे बड़ी संख्या में संगठनों ने सौर ऊर्जा के वैश्विक रूप से विकास और संस्थापना के लिए आईएसए के साथ साझेदारी की संयुक्त घोषणाओं पर हस्ताक्षर किए हैं।

अध्याय

13

राजभाषा हिन्दी को बढ़ावा

राजभाषा हिन्दी को बढ़ावा

13.1 **परिचयः** भारत सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन करने के उद्देश्य से मंत्रालय में एक हिन्दी अनुभाग की स्थापना की गई है जिसके निम्नलिखित कार्य हैं:

» अनुवाद कार्य

» भारत सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन।

13.2 वर्ष 2020–21 के दौरान राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सघन प्रयास किए गए।

13.3 राजभाषा नीति को बढ़ावा देने तथा कार्मिकों के लिए हिन्दी में अधिक कार्य करने हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम और योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

» मंत्रालय की वेबसाइट को द्विभाषी बनाया गया है और उसे समय–समय पर अद्यतन किया जा रहा है।

» मंत्रालय के प्रवेश द्वार पर एक डिजिटल बोर्ड लगाया गया है जिसमें प्रतिदिन हिन्दी का एक नया शब्द प्रदर्शित किया जाता है। प्रेरक वाक्य भी प्रदर्शित किए जाते हैं।

» अधिकारियों और कर्मचारियों की सुविधा के लिए हिन्दी में काम करने के लिए मानक मसौदे और मानक फार्म तैयार किए गए हैं और मंत्रालय की वेबसाइट पर डाले गये हैं।

» मंत्रालय में हिंदी पुस्तकों की खरीद की जाती है और राजभाषा विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयास किए जाते हैं ।

» नोडल एजेंसियों के पते हिंदी में तैयार किए गए हैं।

» राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी कागजात, जैसे– प्रैस विज्ञप्ति, निविदा सूचना, नियम, सामान्य आदेश, अधिसूचनाएं, मंत्रिमंडल टिप्पणी, संसद प्रश्न तथा संसद के समक्ष रखे जाने वाले अन्य सभी दस्तावेज द्विभाषिक रूप में जारी किए जाते हैं।

» हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी में दिया गया और राजभाषा नियम, 1976 के नियम (5) का पूर्ण रुप से अनुपालन किया गया।

13.4 वर्ष 2020–21 के दौरान मंत्रालय में राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अनेक प्रयास किए गए। राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार 'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों के साथ हिन्दी में पत्राचार की प्रतिशतता क्रमशः 75%, 70% और 67% (लगभग) थी।

13.5 राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गई। मंत्रालय के विभिन्न अनुभागों और प्रभागों, इरेडा, सेकी, नीवे, नाइस और नीबे से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा की गई। अनुभागों और प्रभागों तथा अन्य संगठनों को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने की सलाह दी गई।

13.6 हिंदी पखवाड़ा

सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग के प्रति जागरुकता लाने और उसके प्रयोग में वृद्धि लाने के उद्देश्य से मंत्रालय में 14 से 28 सितम्बर, 2020 तक 'हिन्दी पखवाड़ा' मनाया गया। कोविड–19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में, ऑनलाइन प्रतियोगताएं आयोजित की गई, जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों और

मानक प्रचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) को ध्यान में रखा गया। मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्साह से भाग लिया। हिंदी का लगातार प्रयोग करते रहने के संबंध में माननीय गृह मंत्री और माननीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री के संदेश भी पढ़कर सुनाए गए। हिन्दी और हिन्दीतर भाषी कुल 40 अधिकारियों और कर्मचारियों को नकद पुरस्कार दिए गए। मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों और उपक्रमों में भी हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया और ऑनलाइन प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। हिंदी के प्रचार व प्रसार को प्रभावी एवं व्यापक बनाने के लिए मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों और उपक्रमों को आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए गए।

13.7 वर्ष के दौरान राजभाषा विभाग की हिंदी टिप्पण और प्रारूपण प्रोत्साहन योजना को जारी रखा गया और इस योजना के तहत 10 अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया।

13.8 हिंदी सलाहकार समिति के पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है।

13.9 अक्षय ऊर्जा पुरस्कार योजना

नवीकरणीय ऊर्जा के विषयों के संबंध में हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन या हिंदी में अनुदित पुस्तकों को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय में अक्षय ऊर्जा पुरस्कार योजना (विगत में प्राकृतिक ऊर्जा पुरस्कार योजना) कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए प्रथम पुरस्कार के रूप में 1,00,000 रु. द्वितीय पुरस्कार के रूप में 60,000 रु. और तृतीय पुरस्कार के रूप में 40,000 रु. के पुरस्कार का प्रावधान है। हिंदी में अनुदित पुस्तकों के लिए प्रथम, द्वितीय, और तृतीय पुरस्कारों की राशि क्रमशः 50,000 रु., 30,000 रु. और 20,000 रु. है। पुरस्कार विजेताओं को सचिव, एमएनआरई के हस्ताक्षर से प्रशंसा पत्र भी प्रदान किया जाता है।

13.10 हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन

अधिकारियों और कर्मचारियों को अपना सरकारी कामकाज हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए तिमाही–वार हिंदी कार्यशालाएं आयाजित की गई।

13.11 अधीनस्थ कार्यालयों और अनुभागों का निरीक्षण

राजभाषा के प्रगामी प्रयोग से संबंधित स्थिति का जायजा लेने के लिए मंत्रालय के उप निदेशक (राजभाषा) और सहायक निदेशक (राजभाषा) द्वारा समय–समय पर विभिन्न कार्यालयों और स्वायत्त संस्थानों तथा सरकारी उपक्रमों आदि का निरीक्षण किया गया। इस वर्ष के दौरान इरेडा, सेकी और नाइस कार्यालयों का निरीक्षण किया गया।

अनुलग्नक

अनुलग्नक– I

स्टाफ की संख्या

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (प्रशासन)

तालिका 1: दिनांक 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार, **एमएनआरई** में पदों की स्वीकृत संख्या और तैनात संख्या इस प्रकार है:

समूह	क	ख	ग	कुल
स्वीकृत	141	84	85	310
तैनात	79	48	61	188
अनु.जाति	11	10	19	40
अनु.जनजाति	02	02	04	08
ओबीसी	07	10	08	25
दिव्यांग (पीएच)	-	01	01	02

राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (नीवे)

तालिका 2: दिनांक 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार, **राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान** में समूह–वार पदों का विवरण इस प्रकार है:

पदों की सं.	समूह**			कुल
	क	ख	ग	
स्वीकृत	18	13	17	48
तैनात	17	12	17	46
अनु.जाति	02	01	03	06
अनु.जनजाति	01	-	-	01
ओबीसी	03	02	02	07
दिव्यांग (पीएच)	-	01*	-	-

**कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 8.12.2017 के का. ज्ञा. सं. फा.सं. 11012/10/2016 – स्था. क–III के तहत पदों का वर्गीकरण

* विदेश सेवा शर्तों पर प्रतिनियुक्ति

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा)

तालिका 3: दिनांक 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार, **इरेडा** में समूह–वार पदों का विवरण इस प्रकार है

वर्गीकरण	बोर्ड स्तर	समूह क	समूह ख	समूह ग	समूह घ	कुल
तैनात	02	136	01	21	-	160
अनु.जाति	-	17	-	06	-	23
अनु.जनजाति	-	08	-	01	-	09
ओबीसी	-	23	-	03	-	26
दिव्यांग (पीएच)	-	03	-	01	-	04
कुल स्वीकृत संख्या (बोर्ड स्तर से नीचे):						213

सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान (एसएसएस–नीबे)

तालिका 4: दिनांक 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार **(एसएसएस–नीबे)** में समूह वार पदों को विवरण इस प्रकार है:–

समूह	क	ख	ग	घ	कुल
स्वीकृत	21*	01	04	0	26
तैनात	03	01	04	-	08
अनु.जाति	-	-	-	-	-
अनु.जनजाति	-	-	-	-	-
ओबीसी	-	-	-	-	-
दिव्यांग (पीएच)	-	-	-	-	-

* महानिदेशक और 11 वैज्ञानिकों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है।

राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (नाइस)

तालिका 5: दिनांक 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार, **नाइस** में समूह वार पदों का विवरण इस प्रकार है:–

समूह	क	ख	ग	घ	कुल
स्वीकृत	25	16	0	0	41
तैनात	19	08	0	0	27
अनु.जाति	01	01	0	0	02
अनु.जनजाति	0	0	0	0	0
ओबीसी	02	02	0	0	04
दिव्यांग (पीएच)	01	0	0	0	01

टिप्पणी : रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है।

भारतीय सौर ऊर्जा निगम (सेकी)

तालिका 6: दिनांक 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार, **सेकी** में समूह वार पदो का विवरण इस प्रकार है:

समूह	क	ख	ग	घ	कुल
स्वीकृत	122	37	0	0	159
तैनात	90	07	0	0	97
अनु.जाति	07	02	0	0	09
अनु.जनजाति	03	0	0	0	03
ओबीसी	15	02	0	0	17
दिव्यांग (पीएच)	01	01	0	0	02

वेतन एवं लेखा कार्यालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

तालिका 7: दिनांक 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार, **वेतन एवं लेखा कार्यालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय** में स्वीकृत संख्या और तैनात संख्या इस प्रकार है:

समूह	क	ख	ग	घ	कुल
स्वीकृत	3	4	9	0	16
तैनात	3	3	7	-	13
अनु.जाति	1	0	-	-	01
अनु.जनजाति	-	-	1	-	01
ओबीसी	-	-	2	-	02
दिव्यांग (पीएच)	-	-	-	-	-

अनुलग्नक– ।।

लेखा परीक्षा पैरा

वर्ष	रिपोर्ट सं.	अध्याय सं.	पैरा सं.	कार्रवाई	विषय	स्थिति
2018	2018 की 2	IX	9.1	संशोधित एटीएन जोड़ा गया	सौर तापीय संयंत्र का उपयोग न होना	संशोधित एटीएन अपलोड कर दिया गया है।

वर्ष	रिपोर्ट सं.	अध्याय / पैरा सं.	विषय	स्थिति
2020	2020 की 6	XIII/13.1	**कर्नाटक सोलर पावर डवलपमैंट कारपोरेशन लिमिटेड** मौजूदा नियमों के अनुसार इनपुट–पूंजीगत वस्तुओं पर सेनवेट क्रेडिट समय पर उपलब्ध नहीं था, कंपनी को 1.01 करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा और साथ ही खरीदी गई सामग्रियों पर सेनवेट क्रेडिट का लाभ पाने का अवसर भी खोना पड़ा।	कार्रवाई की जा रही है।
2020	2020 की 6	XIII/13.2	**कर्नाटक सोलर पावर डवलपमैंट कारपोरेशन लिमिटेड** भू–स्वामियों को भूमि पट्टा प्रभारों के भुगतान से टीडीएस नहीं लिया गया। यह भू–स्वामियों की ओर से कंपनी द्वारा वहन किया गया, जिसके कारण 5.25 करोड़ रुपए का अनियमित व्यय हुआ।	

अनुलग्नक–III

तालिका 1: वित्त वर्ष 2020–21 में एचआरडी कार्यक्रम के तहत कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी की गई धनराशि (31.12.2020 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	स्वीकृति सं.	एजेंसी का नाम	स्वीकृति की तारीख	धनराशि (रुपए)
1.	342–11/2/2018–एचआरडी	राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, ग्रुरुग्राम	17.11.2020	20,03,653/–
2.	342–11/5/2020–एचआरडी		22.12.2020	59,81,004/–
3.	10/1(26)/2015–पीएंडसी		29.12.2020	8,00,00,000/–

तालिका 2: दिनांक 01.01.2020 से 31.12.2020 तक हरित ऊर्जा गलियारे में राज्यों के पीआईए को 50 लाख से अधिक का अनुदान

क्र. सं.	स्वीकृति सं.	परियोजना/संगठन का नाम	राज्य	जारी धनराशि	
				स्वीकृति की तारीख	धनराशि (लाख रुपए)
1	367–1 1/26/2017–जीईसी	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	हिमाचल प्रदेश	20.02.2020	155.84
2	367–1 1/26/2017–जीईसी	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	हिमाचल प्रदेश	29.04.2020	2690.36

3	367–1 1/26/2017–जीईसी	हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश	29.04.2020	2164.00
4	1/7/2015–ईएफएम	ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश लिमिटेड	आंध्र प्रदेश	29.04.2020	2352.70
	कुल				**7362.90**

तालिका 3: सेकी द्वारा एसपीपीडी/एसटीयू/सीटीयू को जारी की गई संचित सीएफए (लाख रु.में) दिनांक 31.12.2020 की स्थिति

क्र.सं.	राज्य	सौर पार्क	वितरित कुल सीएफए
1	अंडमान एवं निकोबार	एनटीपीसी	0.00
2	आंध्र प्रदेश	अनंनपुरमु–I सोलर पार्क	13525.00
3		कर्नूल सोलर पार्क	12625.00
4		कडप्पा सोलर पार्क	5425.00
5		अनंतपुरुमु–II सोलर पार्क	5124.80
6		हाइब्रिड सोलर विंड पार्क	25.00
7		एक्सटे. ट्रांस. पीजीसीआईएल – आं.प्र.	10955.54
8		एक्सटे. ट्रांस. एपीएक्सटे. ट्रांको–एपी II	4000.00
9		एक्सटे. ट्रांस. एपीएक्सटे. ट्रांको–कर्नूल	7400.00
10	अरुणाचल प्रदेश	लोहित सोलर पार्क	19.65
11	असम	असम में सोलर पार्क	0.00
12	छत्तीसगढ़	राजनंदगांव सोलर पार्क	15.00
13	गुजरात	राधनेसदा सोलर पार्क	3311.35
14		हरसाद सोलर पार्क	0.00
15		धोलेरा सोलर पार्क	0.00
16		एक्सटे. ट्रांस. पीजीसीआईएल –राधनेसदा	2800.00
17	हरियाणा	हरियाणा में सोलर पार्क	0.00
18	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश में सोलर पार्क	0.00
19	जम्मू व कश्मीर	जेएंडके में सोलर पार्क	0.00
20	कर्नाटक	पवागडा सोलर पार्क	18525.44
21		एक्सटे. ट्रांस. पीजीसीआईएल –पवागडा	12000.00
22	केरल	कासरगोड सोलर पार्क	873.94
23	मध्य प्रदेश	रीवा सोलर पार्क	7633.51
24		नीमच मंदसौर सोलर पार्क	2548.50
25		अगार सोलर पार्क	0.00
26		याजापुर सोलर पार्क	0.00
27		मोरेना (चंबल) सोलर पार्क	0.00
28		एक्सटे. ट्रांस. पीजीसीआईएल –रीवा	6000.00
29	महाराष्ट्र	साईं गुरु सोलर पार्क (प्रगट)	435.00
30		पटोडा सोलर पार्क (पैरामाउंट)	25.00
31		डोंडाइचा सोलर पार्क	625.00
32		लातूर सोलर पार्क	10.00
33		वाशिम सोलर पार्क	15.00
34		यावतमल सोलर पार्क	10.00
35		कचराला सोलर पार्क	15.00

36	मणिपुर	बुक्पी सोलर पार्क	10.00
37	मघालय	मेघालय में सोलर पार्क	3.07
38	मिजोरम	वंकल सोलर पार्क	10.00
39	नागालैंड	नागालैंड में सोलर पार्क	10.00
40	ओडिशा	ओडिशा में सोलर पार्क	0.00
41		एनएचपी द्वारा सोलर पार्क	0.00
42	राजस्थान	भाडला–II सोलर पार्क	6120.00
43		भाडला–III सोलर पार्क	10921.15
44		भाडला–IV सोलर पार्क	6018.46
45		फलोदी – पोखरन फतेहगढ़	1825.00
46		फतेहगढ़ फेज–1बी सोलर पार्क	25.00
47		नोख सोलर पार्क	3968.96
48		आरवीपीएन– भा–II, भा –III, भा –IV	10747.10
49		पीजीसीआईएल– भा –II, भा –III, भा IV, पीपी	6000.00
50	तमिलनाडु	तमिलनाडु में सोलर पार्क	0.00
51	तमिलनाडु	कडालाडी सोलर पार्क	25.00
52	तेलंगाना	गद्दू सोलर पार्क	25.00
53	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश में सोलर पार्क	2081.80
54		उत्तर प्रदेश कानपुर देहात सोलर पार्क	0.00
55		उत्तर प्रदेश जालौन सोलर पार्क	0.00
56		उत्तर प्रदेश कानपुर नगर सोलर पार्क	0.00
57		एक्सटे. ट्रांस. यूपीपीटीसीएल	1719.15
58	उत्तराखंड	उत्तराखंड में सोलर पार्क	8.25
59	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल में सोलर पार्क	25.00
कुल			**163485.67**

प्रदान की गयी वित्तीय सहायता अनंतिम और अलेखापरीक्षित है।

तालिका 4: 2000 मेगावाट वीजीएफ योजना के तहत सेकी को दिनांक 01.01.2020 से 31.12.2020 तक जारी धनराशि

2000 मेगावाट वीजीएफ योजना

क्र. सं.	स्वीकृति सं.	एजेंसी का नाम	स्वीकृति की तारीख	धनराशि (रुपए)
1	फा. सं. 283/70/2017–ग्रिड सौर	सेकी	30.06.2020	51,00,00,000
2	फा. सं. 283/70/2017–ग्रिड सौर	सेकी	28.08.2020	30,69,93,027
3	फा. सं. 283/70/2017–ग्रिड सौर	सेकी	28.08.2020	18,45,53,638
4	फा. सं. 283/70/2017–ग्रिड सौर	सेकी	28.08.2020	7,48,60,774
5	फा. सं. 283/70/2017–ग्रिड सौर	सेकी	22.12.2020	19,76,49,288
6	फा. सं. 283/70/2017–ग्रिड सौर	सेकी	22.12.2020	2,10,03,653
7	फा. सं. 283/70/2017–ग्रिड सौर	सेकी	22.12.2020	3,64,73,010

तालिका: 5 केनाल बैंक और कैनाल टॉप पर ग्रिड संबद्ध सौर पीवी विद्युत संयंत्रों के विकास के लिए प्रायोगिक–सह– प्रदर्शन परियोजना' के तहत वित्त वर्ष 2020–21 में 31.12.2020 तक जारी की गई धनराशि

क्र.सं.	स्वीकृति सं.	एजेंसी का नाम	स्वीकृति की तारीख	धनराशि (रुपए)
1	283/7/2017–ग्रिड सौर	भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड (सेकी)	31.08.2020	19,29,27,287

तालिका: 6 'सूर्य मंदिर, कस्बा मोधेरा, जिला – मेहसाना, गुजरात के सौरीकरण की योजना' के तहत तहत वित्त वर्ष 2020–21 में 31.12.2020 तक जारी की गई धनराशि

क्र.सं.	स्वीकृति सं.	एजेंसी का नाम	स्वीकृति की तारीख	धनराशि (रुपए)
1	32/4/2018–एसपीवी प्रभाग	गुजरात पावर कारपोरेशन लिमिटेड (जीपीसीएल)	29.09.2020	16,25,00,000

तालिका: 7 'सीपीएसयू योजना चरण–।।' के तहत वित्त वर्ष 2020–21 में 31.12.2020 तक जारी की गई धनराशि

क्र.सं.	स्वीकृति सं.	एजेंसी का नाम	स्वीकृति की तारीख	धनराशि (रुपए)
1	302/4/2017–ग्रिड सौर	भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड (सेकी)	29.09.2020	115,00,00,000
2	302/4/2017–ग्रिड सौर	भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड (सेकी)	20.10.2020	191,48,45,000
3	302/4/2017–ग्रिड सौर	भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड (सेकी)	27.10.2020	019,79,60,000

तालिका: 8 भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड को भारत सरकार के पूर्णतः सेवित बॉण्ड पर ब्याज के भुगतान के लिए वित्त वर्ष 2020–21 में 31.12.2020 तक जारी की गई धनराशि

क्र.सं.	स्वीकृति सं.	एजेंसी का नाम	स्वीकृति की तारीख	धनराशि (रुपए)
1.	सं.340–12/2/2018–इरेडा	भारतीस अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लि. (इरेडा)	27.07.2020	62,61,32,617

तालिका: 9 सौर फोटोवोल्टेक (ऑफ–ग्रिड सौर प्रभाग): दिनांक 31.12.2020 तक 50 लाख से अधिक जारी की गई धनराशि

क्र. सं.	स्वीकृति सं.	परियोजना/संगठन	राज्य	जारी धनराशि	
				तारीख	(धनराशि रुपए में)
1	32/1/2020–एसपीवी प्रभाग	तेलंगाना नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास निगम लिमटेड	तेलंगाना	06-07-2020	1,70,00,000
2	32/15/2020–एसपीवी प्रभाग	मणिपुर रिन्यूएबल एनर्जी डवलपमैंट एजेंसी	मणिपुर	01-09-2020	66,00,000
3	32/16/2017–18/पीवीएसई (खंड–1)	एम.पी. ऊर्जा विकास लि, भोपाल	मध्य प्रदेश सरकार	06-07-2020	12,93,71,389
4	32/21/2019–एसपीवी प्रभाग	महानिदेशक, आईटीबीपी बल	विभिन्न राज्य	30-06-2020	3,14,55,430
5	32/25/2018–एसपीवी प्रभाग	उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी	उत्तर प्रदेश सरकार	03-12-2020	17,00,00,000
6	32/59/2017–एसपीवी प्रभाग	उत्तराखंड नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी	उत्तराखंड	01-10-2020	1,01,52,261
7	32/60/2017–एसपीवी प्रभाग	उत्तराखंड नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी	उत्तराखंड	01-10-2020	55,16,072
8	32/60/2018–एसपीवी प्रभाग	अंडमान और निकोबार प्रशासन (विद्युत विभाग)	अंडमान और निकोबार	29-05-2020	60,00,000

9	32/63/2017–एसपीवी प्रभाग	उत्तराखंड नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी	उत्तराखंड	01-10-2020	63,06,564
10	32/64/2018–एसपीवी प्रभाग	कर्नाटक रिन्यूएबल एनर्जी डवलपमैंट लिमि,	कर्नाटक	31-07-2020	4,79,32,695
11	32/11/2020–एसपीवी प्रभाग	हरियाणा नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी –(हरेडा)	हरियाणा	29-05-2020	1,05,47,508
12	32/12/2020–एसपीवी प्रभाग	कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार	उत्तर प्रदेश सरकार	30-04-2020	76,70,797
13	32/11/2020–एसपीवी प्रभाग	हरियाणा नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी –(हरेडा)	हरियाणा	29-05-2020	25,31,40,192
14	32/12/2020–एसपीवी प्रभाग	कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार	उत्तर प्रदेश सरकार	30-04-2020	14,57,45,144
15	32/13/2020–एसपीवी प्रभाग	झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी	झारखंड	19-05-2020	12,03,55,920
16	32/14/2020–एसपीवी प्रभाग	कृषि विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार	हिमाचल प्रदेश	30-04-2020	2,79,87,960
17	32/17/2020–एसपीवी प्रभाग	ओडिशा नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी	ओडिशा	01-10-2020	76,56,503
18	32/19/2020–एसपीवी प्रभाग	गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	गुजरात	31-07-2020	3,95,00,000
19	32/20/2020–एसपीवी प्रभाग	त्रिपुरा रिन्यूएबल एनर्जी डवलपमैंट एजेंसी	त्रिपुरा	31-08-2020	3,96,00,000
20	32/21/2020–एसपीवी प्रभाग	कर्नाटक रिन्यूएबल एनर्जी डवलपमैंट एजेंसी	कर्नाटक	31-08-2020	1,26,00,000
21	32/22/2020–एसपीवी प्रभाग	पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी	पंजाब	31-08-2020	8,28,00,000

तालिका 10: वर्ष 2020–21 के दौरान (31.12.2020 तक) निजी, और स्वैच्छिक संगठनों और राज्य पीआईए को प्राप्त 50.00 लाख से अधिक का अनुदान

(क) राज्य परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां –

क्र. सं.	स्वीकृति सं.	परियोजना/संगठन	राज्य	संगठन/एजेंसी	जारी धनराशि		अभियुक्ति
					तारीख	(लाख रु.में)	
1	5/10/2015–एसएचपी	कारगिल रिन्युएबल एनर्जी डवलपमैंट एजेंसी (करेडा) द्वारा 44 डीपीआर तैयार करना	लद्दाख संघ प्रदेश प्रशासन	कारगिल रिन्युएबल एनर्जी डवलमैंट एजेंसी (करेडा)	20.04.2020	**55.95**	सीएफए की दूसरी और अंतिम किश्त की शेष राशि जारी
2	289/2/2017–एसएचपी	टेरेई एसएचपी(3.00 मे. वा.) ममित जिला का नवीकरण और आधुनिकीकरण	मिजोरम	विद्युत और बिजली विभाग, मिजोरम सरकार	28.05.2020	**60.04559**	तीसरी किश्त जारी

3	285/2/2017–एसएचपी	हाइड्रोपावर विकास विभाग (डीएचपीडी) द्वारा 56 डीपीआर तैयार करना	अरुणाचल प्रदेश	हाइड्रोपावर विकास विभाग (डीएचपीडी)	02.07.2020	**165.89**	सीएफए की दूसरी और अंतिम किश्त जारी
4	285/17/2017–एसएचपी	उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूरेडा) द्वारा 07 डीपीआर तैयार करना	उत्तराखंड	उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूरेडा)	27.08.2020	**8.94937**	सीएफए की दूसरी और अंतिम किश्त जारी
5	285/9/2017–एसएचपी	उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूरेडा) द्वारा 06 डीपीआर तैयार करना	उत्तराखंड	उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूरेडा)	31.08.2020	**7.25858**	सीएफए की दूसरी और अंतिम किश्त जारी
6	285/10/2017–एसएचपी	उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूरेडा) द्वारा 14 डीपीआर तैयार करना	उत्तराखंड	उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूरेडा)	14.09.2020	**33.70096**	सीएफए की दूसरी और अंतिम किश्त जारी
7	285/8/2017–एसएचपी	उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूरेडा) द्वारा 11 डीपीआर तैयार करना	उत्तराखंड	उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूरेडा)	14.09.2020	**28.53821**	सीएफए की दूसरी और अंतिम किश्त जारी
8	290/23/2017–एसएचपी	उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूरेडा) द्वारा 09 डीपीआर तैयार करना	उत्तराखंड	उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूरेडा)	12.10.2020	**42.45**	सीएफए की दूसरी और अंतिम किश्त जारी
9	285/11/2017–एसएचपी	उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूरेडा) द्वारा 17 डीपीआर तैयार करना	उत्तराखंड	उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूरेडा)	12.10.2020	**67.60160**	सीएफए की दूसरी और अंतिम किश्त जारी

10	285/12/2017–एसएचपी	उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूरेडा) द्वारा 14 डीपीआर तैयार करना)	उत्तराखंड	उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूरेडा)	19.10.2020	**6.39632**	सीएफए की दूसरी और अंतिम किश्त जारी
11	289/51/2017–एसएचपी	जूमागढ़ एसएचपी (1.2 मे.वा.), चमोली जिला का नवीकरण और आधुनिकीकरण	उत्तराखंड	उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूरेडा)	07.12.2020	**70.00**	सीएफए की दूसरी और तीसरी किश्त जारी
	कुल					**547.78063**	
(ख) निजि क्षेत्र –							
1	287/42/2017–एसएचपी	सोमसिला एसएचपी (8मे. वा)	आंध्र प्रदेश	मैसर्स बालाजी एनर्जी प्रा.लि.	29.05.2020	**500.00**	सब्सिडी की पूरी और अंतिम किश्त जारी
2	287/20/2018–एसएचपी	गुल्लू एसएचपी (24.0 मे.वा.)	छत्तीसगढ़	मैसर्स छत्तीसगढ हाइड्रो पावर एलएलपी	13.08.2020	**250.00**	सब्सिडी की दूसरी और अंतिम किश्त जारी
3	287/239/2017–एसएचपी	गोशीखुर्द एसएचपी (24 मे.वा.)	महाराष्ट्र	मैसर्स महाती हाइड्रो पावर विदर्भ प्रा.लि.	13.08.2020	**500.00**	सब्सिडी की पूरी और अंतिम किश्त जारी
4	287/62/2017–एसएचपी	कोटागा एसएचपी (3.5 मे.वा.)	हिमाचल प्रदेश	मैसर्स शिवा एनर्जी रिसोर्स प्रा. लि.	25.08.2020	**200.00**	सब्सिडी की दूसरी और अंतिम किश्त जारी
5	287/4/2018–एसएचपी	सोमसिला एसएचपी (3.0 मे.वा)	आंध्र प्रदेश	मैसर्स बालाजी एनर्जी प्रा.लि..	30.09.2020	**300.00**	सब्सिडी की दूसरी और अंतिम किश्त जारी
			कुल			**1950.00**	

तालिका 11: 'औद्योगिक, संस्थागत और वाणिज्यक प्रतिष्ठानों में सामुदायिक कूकिंग, प्रोसेस हीट और स्पेस हीटिंग एवं कूलिंग अनुप्रयोगों के लिए ऑफ ग्रिड और विकेन्द्रीकृत संकेंद्रित सौर तापीय (सीएसटी) प्रोद्योगिकियां' कार्यक्रम के तहत वर्ष 2019 में कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी धनराशि (दिनांक 31.12.2020 की स्थिति)

क्र. सं.	स्वीकृति सं.	एजेंसी का नाम	जारी करने की तारीख	धनराशि (रु.)
1.	271/2/2019–सीएसटी	मैसर्स मेगावाट सोल्यूसंश प्रा. लि.	24.07.2020	22,80,000
2.	271/5/2019– सीएसटी	मैसर्स मेगावाट सोल्यूसंश प्रा. लि.	24.07.2020	36,00,000

तालिका 12: आरटीएस कार्यक्रम के चरण–।। के तहत किए गए व्यय का एजेंसी–वार और स्वीकृति–वार ब्यौरा (दिनांक 31.12.2020 की स्थिति)

क्र सं.	पीएफएमएस के अनुसार एजेंसी का ब्यौरा	स्वीकृति संख्या	स्वीकृति की तारीख	धनराशि
1.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम	318/24/2020–ग्रिड कनेक्टेड रुफटॉप	31–08–2020	2,74,68,000
2.	कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रचालन प्रभाग सं.2, यूटी., चंडीगढ़	318/15/2020– ग्रिड कनेक्टेड रुफटॉप	23–06–2020	84,60,000
3.	कानपुर विद्युत आपूर्ति निगम	318/25/2020– ग्रिड कनेक्टेड रुफटॉप	11–11–2020	91,20,000
4.	मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	318/40/2020– ग्रिड कनेक्टेड रुफटॉप	14–12–2020	3,10,13,400
5.	मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	318/40/2020– ग्रिड कनेक्टेड रुफटॉप – खंड (1)	29–12–2020	1,34,75,400
6.	मध्यांचल विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	318/25/2020– ग्रिड कनेक्टेड रुफटॉप	13–11–2020	4,33,20,000
7.	नार्दर्न पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी ऑफ तेलंगाना लिमिटेड	318/19/2020– ग्रिड कनेक्टेड रुफटॉप – खंड (1)	31–12–2020	1,26,00,000
8.	नार्दर्न पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी ऑफ तेलंगाना लिमिटेड	318/19/2020– ग्रिड कनेक्टेड रुफटॉप – खंड(1)	26–08–2020	46,80,000
9.	पश्चिम गुजरात विज कंपनी लिमिटेउ	318/69/2019– ग्रिड कनेक्टेड रुफटॉप –	21–04–2020	78,52,475
10.	पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड	318/19/2020– ग्रिड कनेक्टेड रुफटॉप –	24–07–2020	3,33,00,000
11.	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	318/25/2020– ग्रिड कनेक्टेड रुफटॉप –	23–11–2020	2,28,00,000
12.	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड	318/32/2020– ग्रिड कनेक्टेड रुफटॉप –	15–10–2020	89,47,800
13.	नार्दर्न पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी ऑफ तेलंगाना लिमिटेड	318/19/2020– ग्रिड कनेक्टेड रुफटॉप – खंड (1)	31–12–2020	5,04,00,000
14.	नार्दर्न पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी ऑफ तेलंगाना लिमिटेड	318/19/2020– ग्रिड कनेक्टेड रुफटॉप – खंड (1)	26–08–2020	3,36,33,600
15.	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम	318/24/2020– ग्रिड कनेक्टेड रुफटॉप –	31–08–2020	1,37,34,000
16.	उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड	318/26/2020– ग्रिड कनेक्टेड रुफटॉप –	31–08–2020	3,52,08,000

तालिका 13: आरटीएस कार्यक्रम के चरण–I के तहत किए गए व्यय का एजेंसी–वार और स्वीकृति–वार ब्यौरा (दिनांक 31.12.2020 की स्थिति)

क्र सं.	पीएफएमएस के अनुसार एजेंसी का ब्यौरा	स्वीकृति संख्या	स्वीकृति की तारीख	धनराशि
1	सैंट्रल इलैक्ट्रॉनिक्स लि.	318/15/2017– ग्रिड कनेक्टेड रुफटॉप – खंड(1)	30–06–2020	2,87,33,121
2	सैंट्रल इलैक्ट्रॉनिक्स लि.	318/53/2018– ग्रिड कनेक्टेड रुफटॉप – खंड(5)	12–10–2020	3,56,69,415
3	सैंट्रल इलैक्ट्रॉनिक्स लि.	318/15/2017– ग्रिड कनेक्टेड रुफटॉप – खंड(1)	08–04–2020	1,73,76,482
4	दिल्ली मैट्रा रेल निगम	318/51/2018– ग्रिड कनेक्टेड रुफटॉप	30–04–2020	6,20,82,153
5	गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लिमिटेड	318/50/2019– ग्रिड कनेक्टेड रुफटॉप	31–07–2020	3,08,517
6	इंडिया एसएमई टैक्नोलोजी सर्विसेज लिमिटेड	318/20/2018– ग्रिड कनेक्टेड रुफटॉप – खंड(3)	27–10–2020	2,63,29,108
7	इंडिया एसएमई टैक्नोलोजी सर्विसेज लिमिटेड	318/15/2017– ग्रिड कनेक्टेड रुफटॉप – खंड(4)	31–12–2020	15,22,37,470
8	इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड	318/20/2018– ग्रिड कनेक्टेड रुफटॉप – खंड(7)	02–11–2020	6,32,10,007
9	इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड	318/68/2019–जीसीआरटी	10–04–2020	14,74,27,824
10	जम्मू एंड कश्मीर डवलपमैंट एजेंसी	318/53/2018– ग्रिड कनेक्टेड रुफटॉप – खंड(2)	09–04–2020	4,89,12,192
11	महाराष्ट्र एनर्जी डवलपमैंट एजेंसी	318/35/2017– ग्रिड कनेक्टेड रुफटॉप	24–12–2020	18,08,17,330
12	महाराष्ट्र एनर्जी डवलपमैंट एजेंसी	318/20/2018– ग्रिड कनेक्टेड रुफटॉप	29–12–2020	36,97,95,573
13	मणिपुर रिन्यूएबल एनर्जी डवलपमैंट एजेंसी	318/19/2019– ग्रिड कनेक्टेड रुफटॉप	23–07–2020	4,03,18,600
14	न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डवलपमैंट कारपोरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश लिमिटेड	318/61/2019– ग्रिड कनेक्टेड रुफटॉप	30–04–2020	19,88,80,251.00
15	न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डवलपमैंट कारपोरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश लिमिटेड	318/20/2018– ग्रिड कनेक्टेड रुफटॉप – खंड(5)	20–04–2020	7,92,17,861
16	नोयडा मैट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड	318/14/2020– ग्रिड कनेक्टेड रुफटॉप	28–05–2020	8,74,49,999
17	नार्दर्न रेलवे	318/61/2018– ग्रिड कनेक्टेड रुफटॉप	21–04–2020	3,68,37,000
18	पंजाब एनर्जी डवलपमैंट एजेंसी	318/22/2018– जीसीआरटी	22–06–2020	3,54,07,320
19	राजस्थान इलैक्ट्रानिक्स एंड इंस्ट्रूमैंट्स लिमिटेड	318/75/2019– ग्रिड कनेक्टेड रुफटॉप	02–06–2020	2,89,30,845
20	राजस्थान इलैक्ट्रानिक्स एंड इंस्ट्रूमैंट्स लिमिटेड	318/22/2019– ग्रिड कनेक्टेड रुफटॉप	11–08–2020	7,01,55,169

21	राजस्थान इलैक्ट्रानिक्स एंड इंस्ट्रूमैंट्स लिमिटेड	318/75/2019– ग्रिड कनेक्टेड रुफटॉप	28–08–2020	2,91,29,303
22	राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कारपोरेशन लिमिटेड	318/338/2017– ग्रिड कनेक्टेड रुफटॉप	09–04–2020	11,59,66,395
23	भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड	318/234/2017– ग्रिड कनेक्टेड रुफटॉप	31–08–2020	8,88,90,564
24	भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड	318/234/2017–जीसीआरटी	29–10–2020	22,54,34,089
25	भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड	318/234/2017–जीसीआरटी	16–04–2020	21,54,87,730
26	तमिलनाडु एनर्जी डवलपमैंट एजेंसी	318/212/2017– ग्रिड कनेक्टेड रुफटॉप	29–12–2020	4,41,39,692
27	तेलंगाना न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी कारपोरेशन लिमिटेड	318/77/2018– ग्रिड कनेक्टेड रुफटॉप	26–08–2020	5,88,15,614
28	तेलंगाना न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी कारपोरेशन लिमिटेड	318/53/2018– ग्रिड कनेक्टेड रुफटॉप – खंड(4)	31–07–2020	4,64,83,125
29	उत्तरप्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डवलपमैंट लिमिटेड	318/89/2018– ग्रिड कनेक्टेड रुफटॉप	23–12–2020	7,15,36,340
30	उतराखंड एनर्जी डवलपमैंट एजेंसी	318/30/2017– ग्रिड कनेक्टेड रुफटॉप	31–12–2020	1,03,09,659

तालिका 14: दिनांक 07.01.2021 की स्थिति के अनुसार वित्त वर्ष 2020–21 के लिए नवीन राष्ट्रीय बायोगैस जैव खाद कार्यक्रम (एनएनबीओएमपी) एवं बायोगैस विद्युत (ऑफ–ग्रिड) उत्पादन और तापीय कार्यक्रम (बीपीजीटीपी) के तहत कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी धनराशि

क्र. सं.	कार्यान्वयन एजेंसी	एमएनआरई द्वारा दिनांक 07.01.2021 तक जारी धनराशि
1.	राज्य नोडल अधिकारी एफडीए –सह– अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, असम, गुवाहाटी	2,90,00,000
2.	कृषि निदेशालय, गोवा सरकार	5,70,350
3.	मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड (एमपीएसएआईडीसी), भोपाल	4,80,76,015
4.	**मेघालय अपारंपरिक एवं ग्रामीण ऊर्जा विकास एजेंसी (मनरेडा), शिलांग**	10,00,000
5.	ग्रामीण विकास विभाग, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई	2,10,00,000
6.	ग्रामीण विकास विभाग, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह प्रशासन (संघ शासित क्षेत्र)	6,00,000
7.	राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आनंद(गुजरात)	1,20,00,000
8.	न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डवलपमैंट कारपोरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश, टेडेपल्ली, जिला गुटूर, आंध्र प्रदेश	5,50,47,862
9.	ओडिशा रिन्यूएबल एनर्जी डवलपमैंट एजेंसी (ओरेडा), भुवनेश्वर	9,72,000

10.	**पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (पेडा), चंडीगढ़**	2,86,36,737
11.	ग्रामीण विकास विभाग, पोड़ी, उत्तराखंड सरकार	30,00,000
12.	ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, कर्नाटक सरकार, बंगलुरु (कर्नाटक)	4,20,00,000
13.	कृषि विकास और किसान कल्याण निदेशालय, तिरुवनंतपुरम, केरल	48,00,000
14.	**खादी और ग्रामोद्योग आयोग, केवीआईसी मुंबई**	30,00,000
15.	उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास (यूपीनेडा), लखनऊ	35,37,200
16.	बीडीटीसी, यूएएस, बंगलुरु	44,94,636
17.	बीडीटीसी, टीएनएयू, कोयंबटूर	36,22,386
18.	जीईडीए, गांधीनगर, गुजरात	17,00,000
19.	बीडीटीसी, आईआईटी, गुवाहाटी	21,27,724
20.	बीडीटीसी, केआईआईटी, भुवनेश्वर	26,12,724
21.	बीडीटीसी, सीईएसआर, इंदौर	23,50,224
22.	बीडीटीसी, एमपीयूएटी, उदयपुर	22,23,312
	कुल	**27,23,71,170**

तालिका 15: निम्नलिखित निजी और स्वैच्छिक संगठनों को अनुसंधान और विकास कार्यक्रम के तहत वर्ष 2020–21 के दौरान 10 लाख रुपए से अधिक का अनुदान प्राप्त हुआ (31.12.2020 की स्थिति)

क्र. सं.	स्वीकृति संख्या	परियोजनाओं / संगठनों का नाम	राज्य	जारी धनराशि	
				तारीख	धनराशि (रु. में)
1	31/8/2019–सौर आर एंड डी	उत्तरांचल विश्वविद्यालय, देहरादून	उत्तराखंड	29.04.2020	30,00,000

तालिका 16: निम्नलिखित शैक्षणिक संस्थानों को हाइड्रोजन और ईंधन सैल कार्यक्रम के तहत वर्ष 2020–21 के दौरान 10 लाख रुपए से अधिक का अनुदान प्राप्त हुआ (20.01.2021 की स्थिति)

क्र. सं.	नाम	जारी धनराशि (रुपए)
1.	योगी वेमेना यूनिवर्सिटी (वाईवीयू), कडप्पा और सैंट्रल इलैक्ट्रो कैमिकल रिसर्च इंस्टिट्यूट (सीईसीआरआई), कराइकुडी	10,00,000
2.	दयालबाग एजुकेशनल इंस्टिट्यूट	2,00,00,000
3.	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस बंगलुरु	80,00,000

टिप्पणियाँ

टिप्पणियाँ

सत्यमेव जयते

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

भारत सरकार